20 मार्च, 2026 वर्ष 35 * पृष्ठ संख्या 72, अंक 03

राजस्थान सुजस

राजस्थान बन रहा

अवसरों की भूमि

शब्द भावना

राजस्थान दिवस

गौरवशाली इतिहास के साथ विकास की नई उड़ान

"

विक्रम सम्वत 2006 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (30 मार्च, 1949) का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इसी पावन तिथि को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर में रेवती नक्षत्र, इन्द्रयोग की शुभ घड़ी में वृहद राजस्थान की स्थापना की थी। इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय संस्कृति में नववर्ष, नवचेतना और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए राजस्थान दिवस ऐतिहासिक घटना के स्मरण के साथ ही हमारी सांस्कृतिक जड़ों, परंपराओं और सामूहिक चेतना का भी उत्सव है। इसी भावना के तहत राजस्थान दिवस पंचांग की तिथि के अनुसार इस वर्ष 19 मार्च को मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए नीतिगत सुधार, पारदर्शी शासन और जनभागीदारी के बल पर विकास व निवेश की नई कहानी लिखता राजस्थान अब नए आत्मविश्वास के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। राजस्थान दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि यह प्रदेश, इतिहास की गौरवगाथाओं होने के साथ ही अनंत संभावनाओं की भूमि भी है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को साकार करने और पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध, सुरक्षित और गौरवशाली राजस्थान के निर्माण में सहभागिता का आह्वान करता हूं।

जय हिन्द ! जय भारत ! जय राजस्थान !

-मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

प्रधान संपादक
राकेश शर्मा

वरिष्ठ संपादक
डॉ. गोरधन लाल शर्मा

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
मोहित जैन

संकलन एवं वितरण
ऋतु शर्मा
रणवीर सिंह कुशवाह

आवरण छाया
अमित सारस्वत

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिन्टर्स
लागत मूल्य 37.00 रुपये

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80581 15790
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

वर्ष : 35, अंक 03

इस अंक में

मार्च, 2026

आपणो अग्रणी राजस्थान **05**

वित्त एवं विनियोग विधेयक पारित **21**

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई पहल **30**

शब्द भावना	02
सम्पादकीय	04
लोकतंत्र की नई धारा में रजवाड़े...	18
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना	27
सशक्त नारी विकास की आधारशिला	32
AI कर रहा चेहरे की पहचान	35
एचपीवी टीकाकरण	43
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग	44
विकसित राजस्थान के संकल्प	46
राजस्थान होम स्टे योजना-2026	50
'वायु शक्ति-2026'	52
डाक जीवन बीमा	53
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024	54
शेखावाटी से लेकर ब्रज तक की होली	56
हरित विकास की ऐतिहासिक पहल	62
कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास	66
सामयिकी	67
प्रश्नोत्तरी नं. – 07	70

प्रधानमंत्री का अजमेर दौरा **36**

एमएसपी पर गेहूं खरीद **48**

कृष्णमृगों की धरा-तालछापर **58**

एआई-एमएल पॉलिसी और एवीजीसी-एक्सआर नीति **64**

संपादकीय

विकास, विरासत और
नवसंकल्पों से आलोकित राजस्थान

30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वृहद् राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में गत वर्ष यह घोषणा की गई कि राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा। इस क्रम में प्रदेश में एक बार फिर अपनी गौरवशाली विरासत, सशक्त संकल्पों और निरंतर प्रगति की दिशा में बढ़ते कदमों का उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 को मनाया गया। 14 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित राजस्थान उत्सव-2026 केवल परंपराओं को स्मरण करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें विकास, विश्वास और जनसहभागिता के सशक्त समन्वय को भी रेखांकित किया गया। 'स्वच्छता शपथ', 'विकसित राजस्थान रन', 'सांस्कृतिक कार्यक्रम', 'क्विज', 'महाआरती', 'युवा दिवस', 'उद्यमी संवाद समारोह' और 'विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान' जैसे विविध आयोजनों ने जन-जन को इस उत्सव से जोड़ा।

इसी उत्साह और विकास की सशक्त पृष्ठभूमि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अजमेर दौरा प्रदेश के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर सिद्ध हुआ। इस अवसर पर उनके द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया गया, जो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान को हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदान की गई तथा बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस पहल की गई।

प्रदेश में विकास की इसी निरंतरता के बीच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 11 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात 27 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा बजट में निहित जनकल्याणकारी योजनाओं और विकासोन्मुख नवीन प्रावधानों के माध्यम से प्रदेशवासियों के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया गया। इसी क्रम में विधानसभा द्वारा राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 तथा राजस्थान वित्त विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया, जिससे विभिन्न विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रदेश में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कोटा–बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का शिलान्यास हाड़ौती क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोलने वाला कदम है।

यदि समग्र रूप से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रों की पावन ऊर्जा से आलोकित यह माह राजस्थान के लिए विकास की नई ऊर्जा, युवाओं के सपनों को नई उड़ान और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का नवीन संदेश लेकर आया। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, जनसहभागिता और सतत प्रयासों के साथ नव राजस्थान के गठन की गौरवशाली कहानी तथा राजस्थान दिवस के विविध आयोजनों की झलकियों को समेटे मार्च माह का यह अंक नवसम्वत्सर की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आप सभी सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

वन्दे मातरम् ।

(राकेश शर्मा)
प्रधान सम्पादक

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नवसंवतसर) पर राजस्थान दिवस

म्हारी पहचान, म्हारो मान
आपणो अग्रणी राजस्थान

आ तो सुरगां नै सरमावै, ईं पर देव रमण नै आवै,
ईं रो जस नर नारी गावै, धरती धोरां री!
ईं पर तनड़ो मनड़ो वारां, ईं पर जीवण प्राण उंवारां,
ईं री धजा उड़ै गिगनारां, मायड़ कोड़ां री !
.... धरती धोरां री!

कन्हैया लाल सेठिया जी की ये पंक्तियां राजस्थान की वीरता, साहस, आत्मगौरव और मरुधरा की महिमा को व्यक्त करती हैं। राजस्थान की धरती, वह धरती है जहां समृद्ध विरासत के प्रतीक भव्य महल और प्रासाद खड़े हैं, तो दूसरी ओर अजेय साहस और वीरता की कहानियां सुनाते किले और गढ़ भी मौजूद हैं। जहां माटी, गोबर और घास-फूस से सजे-धजे घरों की दीवारों पर उकेरे गए रंगीन मांडने लोक जीवन की सादगी और सौंदर्य को दर्शाते हैं। बरसात के जल से भरी झीलें इसकी शोभा बढ़ाती हैं, तो अरावली की विस्तृत पर्वतमालाएं मानों इस प्रदेश को अपनी गोद में समेटे खड़ी हैं। दिन की तपिश सहकर रात की चांदनी में चमकती सुनहरी रेत जैसे सोने की आभा बिखेरती है। यहां की हवेलियां अपनी अद्भुत शिल्पकला से मन मोह लेती हैं। मंदिरों और देवालयों में आस्था और कला का अनुपम संगम देखने को मिलता है। इस धरती पर असंख्य रणभूमियां भी हैं, जो मातृभूमि के लिए दिए गए बलिदानों की अमर गाथाएं सुनाती हैं। रेगिस्तान में धीरे-धीरे चलते ऊंटों के काफिले और आकाश में उड़ते पक्षियों के झुंड यहां की जीवनधारा को गति देते हैं। वीरता, भक्ति, नीति और प्रेम के रंगों से सजी यह धरती सच में ऐसी है, जहां हर दिन एक उत्सव है।

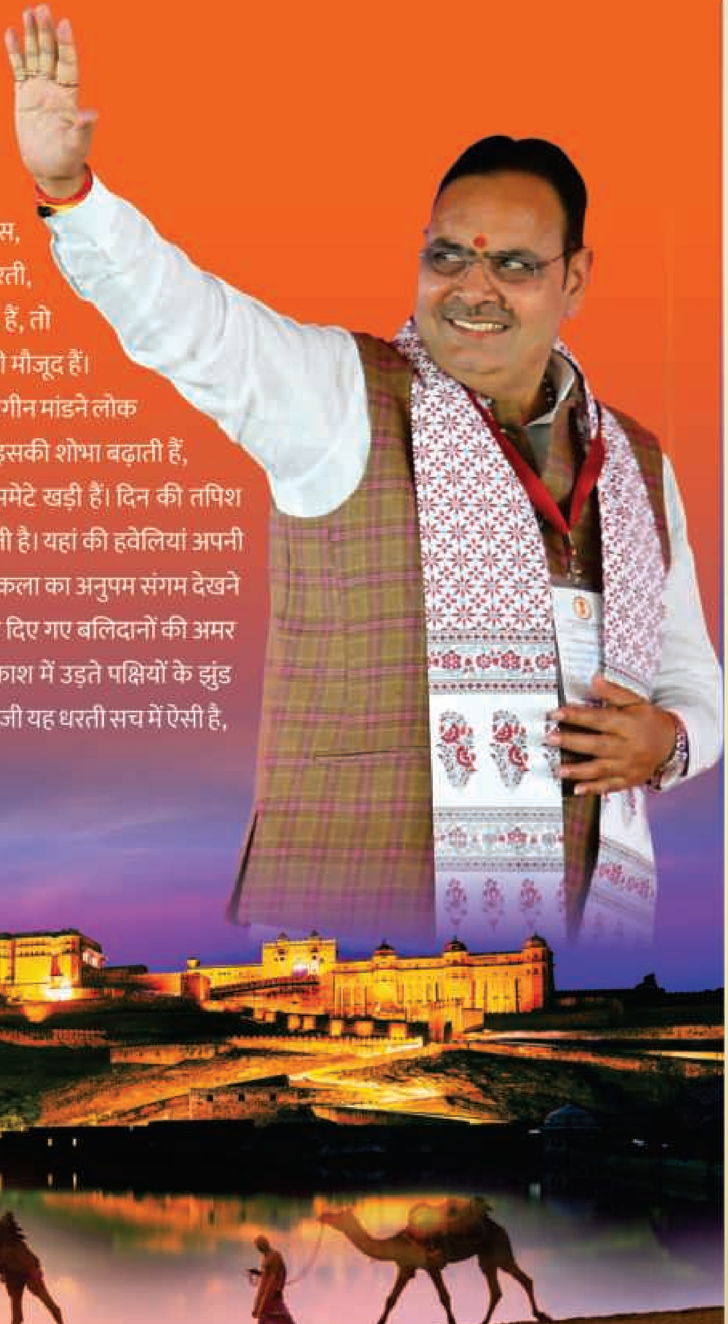

राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष से राजस्थान दिवस को भारतीय तिथि अनुसार मनाने की नई परंपरा शुरू की है। 30 मार्च 1949 को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में विभिन्न रियासतों को एकत्रित कर भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र, इन्द्र योग में वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। ग्रह नक्षत्र देखकर नए कार्य की शुरुआत करना हमारी संस्कृति में है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को राजस्थान दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

संवत परंपरा- विक्रम संवत और शक संवत

भारत की काल गणना परंपरा अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक रही है, जिसमें प्रमुख रूप से विक्रम संवत और शक संवत का विशेष महत्व है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व माना जाता है और इसे परंपरागत रूप से सम्राट विक्रमादित्य की विजय से जोड़ा जाता है। यह संवत मुख्यतः उत्तर भारत और आस पास के क्षेत्रों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिए व्यापक रूप से प्रचलित है। वहीं शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ और इसे भारत सरकार ने आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया है, जिसका उपयोग प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यों में किया जाता है। इन दोनों काल गणनाओं में भारतीय जीवन, ऋतुचक्र और सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी झलक मिलती है। वर्ष 2026 में 19 मार्च को चैत्र नवरात्र स्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ और इसी दिन विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हुआ।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नव संवतसर) का महत्व

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय संस्कृति में नवआरंभ, उत्सव और सृजन का पावन प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं में इसे सृष्टि के प्रारंभ का दिवस भी माना गया है, जब ब्रह्मा जी ने सृजन की प्रक्रिया आरंभ की। राजस्थान की स्थापना का उत्सव भारतीय नववर्ष के साथ समन्वित होकर नवचेतना, आत्मगौरव और सांस्कृतिक अस्मिता के सशक्त प्रतीक के रूप में स्थापित होता है।

विविध भारतीय नव वर्ष पर्व

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्व केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भारत में विविध सांस्कृतिक रूपों में नववर्ष के रूप में मनाई जाती है। देश के विभिन्न भागों में यह तिथि अलग-अलग परंपराओं और नामों के साथ उत्सव का स्वरूप ग्रहण करती है। महाराष्ट्र में इसे **गुड़ी पड़वा** के रूप में मनाया जाता है, जहां नए वर्ष के स्वागत में घरों पर गुड़ी स्थापित की जाती है। सिंधी समाज के लिए यह दिन **चेटीचंड** के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके आराध्य देव झूलेलाल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यही तिथि **उगादी** के रूप में मनाई जाती है, जो नए वर्ष के आगमन और नई आशाओं का प्रतीक है। इस प्रकार, एक ही तिथि का देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूपों में उत्सव के रूप में मनाया जाना भारत की सांस्कृतिक विविधता में निहित एकता को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करता है।

सरदार पटेल ने बताई... राजस्थान की गौरवगाथा

30 मार्च 1949 को अपने भाषण में सरदार पटेल ने कहा था, "आज से हम इस चीज को भूल जाएं कि हमारे बीच में कोई पर्दा है। कोई भेदभाव है। आज सारा राजपूताना एक है। हम उसे एक दृष्टि से देखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। हमने एक बड़ा राजस्थान बनाया है, उसका मतलब क्या है? राजाओं ने अपनी राज-सत्ता छोड़ दी, उसका मतलब क्या है? आपको समझना है कि आज दुनिया जिस तेजी से आगे चल रही है, उस तेजी से हम आगे न चले तो और अधिक पिछड़ जाने वाले हैं। हम अपनी छोटी सी रियासत में या छोटे से किले में बैठकर बाहर की ओर नजर नहीं करेंगे, तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती।"

राजस्थान दिवस-समारोह 2026

इस वर्ष राजस्थान दिवस 2026 उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत 14 मार्च को हुई। इसी श्रृंखला में 15 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य- स्तरीय विकसित राजस्थान रन, 'राजस्थान को जाने' क्विज और राज्य तथा जिला स्तरीय ओ.डी.ओ.पी. मेले एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। 16 मार्च को बेणेश्वर धाम, बांसवाड़ा में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, 17 मार्च को जयपुर में राजस्थान युवा शक्ति दिवस, 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह आयोजित किया गया। 19 मार्च को 207 नवीन रोडवेज बसों की रवानगी और विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसी के साथ अल्बर्ट हॉल पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। इस प्रकार 6 दिनों तक चले उत्सव ने राजस्थान दिवस को राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का जीवंत प्रतीक बना दिया। ■

रन, क्विज़ और प्रदर्शनी

‘विकसित राजस्थान रन-2026’

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में 15 मार्च को जयपुर में अमर जवान ज्योति से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ‘विकसित राजस्थान रन-2026’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

‘राजस्थान को जानें’ क्विज़

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आरकेसीएल एवं शिक्षा विभाग की सहभागिता से ‘राजस्थान को जाने’ क्विज़ के रूप में अनूठी पहल की गई, जिसमें युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। मुख्यमंत्री ने 15 मार्च को सोशल मीडिया हैण्डल एक्स पर पोस्ट करते हुए इस विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की। क्विज़ पूर्ण करने पर प्रतिभागियों को राजस्थान सरकार एवं राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) की ओर से डिजिटल प्रमाण-पत्र भी दिया गया।

ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) प्रदर्शनी

राजस्थान दिवस समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य स्तर और सभी जिलों में ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में सभी जिलों के ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जहां से इनका क्रय-विक्रय भी हुआ। जयपुर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी- 2026 ‘जयपुर रत्नम्’ लगाई गई। ▪

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 14 मार्च को अल्बर्ट हॉल से प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सफाईकर्मियों को पीपीई किट का वितरण किया। साथ ही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चैक भी सौंपे। श्री शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा रामनिवास बाग में पौधारोपण भी किया।

आपणो अग्रणी राजस्थान

"राजस्थान की संस्कृति, लोक परंपराएं और कला-संस्कृति हमारी गौरवशाली पहचान का आधार हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।"

-मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

बीकानेर हाउस, नई दिल्ली

संस्कृति और परंपरा का महोत्सव

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित "राजस्थान उत्सव 2026" का 15 मार्च को भव्य शुभारंभ किया। इस उत्सव में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, लोकसंगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों की झलक प्रस्तुत की गई।

श्री शर्मा ने मेले में राजीविका और ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रूडा) की तरफ से लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और राजीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक वस्त्रों और कलात्मक कृतियों की सराहना करते हुए उनके अनुभव और कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजीविका दीदियों से स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों, उत्पादों की बिक्री और आजीविका के अवसरों के बारे में चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया।

बीकानेर हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रम

बीकानेर हाउस परिसर में श्री शर्मा ने राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के लोकजीवन, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अलवर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर श्री प्रवीण प्रजापत ने पारंपरिक मटका भवाई नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही मनमोहक मयूर नृत्य तथा फूलों की होली की रंगारंग प्रस्तुति ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ■

जनजातीय कला को सम्मान

युवाओं को काम और पहचान

राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस (16 मार्च, 2026)

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। यह दिन आदिवासियों को समर्पित रहा, जिन्होंने राजस्थान की विकास यात्रा में अतुलनीय योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर एवं सिरोही जिले के 1 हजार 902 करोड़ रूपये के 326 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। श्री शर्मा ने लखपति दीदी सम्मान योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों को सांकेतिक चैक और टेबलेट सौंपे। मुख्यमंत्री ने परिसर में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित की।

इससे पहले उन्होंने डूंगरपुर में वाल्मीकि मन्दिर एवं हरि मन्दिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

जनजातीय समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत

जनजातीय समाज अपनी समृद्ध परंपरा, विशिष्ट संस्कृति तथा प्रकृति के साथ गहरे संबंध के लिए प्रसिद्ध है। इस समाज ने ऐसे वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश-प्रदेश का विकास इनकी सक्रिय भागीदारी से ही संभव हो सकेगा। राज्य सरकार जनजातीय समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बेणेश्वर धाम की ऐतिहासिक भूमि आदिवासी आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। राज्य सरकार द्वारा बेणेश्वर धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है।

हस्तशिल्प जनजातीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति

जनजातीय समाज ने अपनी आजादी से कभी समझौता नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा ने महज 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष की अलख जगाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं

जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। राजस्थान का हस्तशिल्प जनजातीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। पिथोरा चित्रकला, बांस की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी आदि सभी राजस्थान की अनमोल सांस्कृतिक विरासत हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इन सभी कलाओं को सम्मान मिले और कलाकारों को इनका उचित मूल्य मिले।

जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक निर्णय

राज्य सरकार प्रदेश में जनजाति उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। छात्रावासों में मैस भत्ता ढाई हजार से बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रति माह किया गया है। साथ ही, खेल अकादमियों में मैस भत्ते में बढ़ोतरी, कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि, सीए व सीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। 244 नए मां-बाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है तथा जनजातीय किसानों को मुफ्त संकर मक्का बीज एवं मिनिकिट का वितरण किया गया है। इसी तरह प्रदेश के 8 जिलों में 530 वन धन विकास केंद्रों का गठन कर डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के जनजाति समाज के खिलाड़ियों ने एशियन लेक्रोस गेम्स, राष्ट्रीय लेक्रोस चैम्पियनशिप सहित विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीते हैं।

वन अधिकार पट्टों के लिए विशेष अभियान

राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन वन अधिकार पट्टों की राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वे इस भूमि पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकें। बेणेश्वर धाम में संगम एवं अबूदरा घाटों के निर्माण एवं वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता बनाये रखने के लिए बेणेश्वर एनिकट की रिमॉडलिंग के कार्य किए जाएंगे। साथ ही आदिवासी बाहुल्य जिलों के ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़धाम, बेणेश्वरधाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट भी विकसित किया जा रहा है। ▪

युवा आगे बढ़ो, मेहनत करो

राज्य सरकार हमेशा आपके साथ

-मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान युवा शक्ति दिवस, 17 मार्च 2026

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' 17 मार्च को आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और खेल से जुड़े 485 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। श्री शर्मा ने युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम लाभार्थी को चैक सौंपा। 403 स्टार्टअप्स को 1 हजार 145 लाख रुपये का वायबिलिटी गैप फंड वितरण तथा 9 हजार 432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र भी सौंपे गए।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

युवा तरुणाई राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है। युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा का उपयोग कर देश दुनिया में सिरमौर बन सकता है। विकसित भारत-विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसान, युवा, महिला और मजदूर के उत्थान के लिए संकल्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री देश के किसान, युवा, महिला और मजदूर, चारों वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देश में विकास एवं गरीब कल्याण की योजनाओं से दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। है। प्रधानमंत्री ने देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप से युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए मंच मिला है तथा उन्हें आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं।

बजट में युवाओं के सशक्तीकरण के ठोस कदम

बजट 2026-27 में भी युवाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। जनजाति क्षेत्र के 5 हजार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही, जयपुर में 'अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग' की स्थापना तथा 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में आईसीटी लैब बनाई जाएंगी। 'एक जिला-एक उत्पाद योजना' के माध्यम से जिले की स्थानीय विशिष्टताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है।

बिजली-पानी-रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्णय

राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। पानी जैसी बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी, गंगनहर, माही सहित कई परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश में बिजली तंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। राजस्थान में अभी कृषि क्षेत्र में 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है, 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली देने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

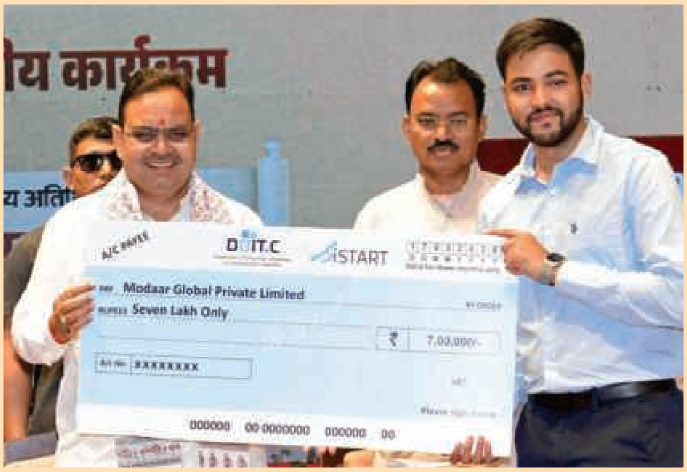

युवा नीति से उद्यमिता को मिल रहा बढ़ावा

युवाओं के लिए राज्य सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता बनें। राज्य सरकार युवाओं को 4 लाख सरकारी क्षेत्र में एवं 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख 33 हजार भर्ती प्रक्रियाधीन हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है। ■

आपणो अग्रणी राजस्थान

उद्यमी संवाद समारोह, 18 मार्च 2026

ईज ऑफ डूइंग से बिजनेस और निवेश को मिली गति

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी संवाद समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया। उन्होंने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े 119 करोड़ रुपये लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में श्री शर्मा ने एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चैक सौंपे। साथ ही, एमएसएमई नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, आरएफसी की युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिए। इस अवसर पर रीको के ऋण स्वीकृति पत्र, जोधपुर-पाली-मारवाड़ और बूढ़ी बावल औद्योगिक क्षेत्रों के आरक्षण पत्र सहित लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी प्रदान किए गए। वहीं, सीएसआर के तहत एसएमएस हॉस्पिटल और 'अपना घर' को सांकेतिक चैक सौंपे गए। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं से लाभ ले रहे युवा उद्यमियों ने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रहे हैं एवं गरीब, युवा, महिला एवं किसान के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार भी इस संकल्प को ध्येय मानते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े माध्यम हैं तथा उद्यमी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और निरन्तर नीतिगत सुधार किए हैं, जिससे राजस्थान औद्योगिक विकास की एक नई गाथा लिख रहा है।

अनुकूल नीतियों से बदला प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य

राज्य सरकार के ठोस एवं दूरदर्शी निर्णयों से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' में हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के कार्य धरातल पर शुरू हो चुके हैं। हाल ही में, होंडा द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए किया गया एमओयू प्रदेश में बढ़ते हुए विश्वास का प्रमाण है। बीकानेर, पाली, किशनगढ़, जोधपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं। वहीं, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भू आवंटन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निकट सलारपुर और बिचून में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए गए हैं।

14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध

राज्य सरकार की निवेशपरक नीतियों के कारण राजस्थान तेजी से एक प्रमुख औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। 'रिप्स 2024' के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया गया है तथा भूमि उपयोग परिवर्तन की समय-सीमा 60 से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। राजनिवेश पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़कर 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं। 'राज्य कौशल नीति' और 'राजस्थान युवा नीति' के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

बजट में औद्योगिक विकास के अनेक प्रावधान

बजट 2026-27 में प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। निवेशकों की सुविधा के लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी जारी की गई है तथा सभी संभागीय मुख्यालयों पर 'प्लग एंड प्ले फैसेलिटी' स्थापित की जाएगी। 600 करोड़ रुपये से जोधपुर-पाली-मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों के लिए डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सिंगल विण्डो 2.0 प्लेटफार्म लागू करने, आई.एफ.एम.एस. और आर.आई.पी.एस पोर्टल का इंटीग्रेशन, सर्विस सेक्टर को भी रिप्स-2024 के तहत इन्टरेस्ट सबवेंशन का लाभ देने तथा एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर निर्माण जैसे विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिससे उद्यमियों को प्रदेश में अपना उद्यम स्थापित करने में सुगमता हो।

तीन नवीन नीतियों से औद्योगिक विकास को नई दिशा

पिछले सवा दो साल में राज्य सरकार ने 34 नई नीतियां लागू की हैं, जिससे उद्यमियों को निवेश के लिए बेहतर वातावरण मिला है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी निवेशकों को बुनियादी ढांचा तैयार कराने में मददगार होगी। साथ ही, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी से प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगा। राज्य सरकार ने भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। यह नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। ये तीनों नीतियां राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम बनेंगी। ■

आमजन के लिए अधिक सुगम एवं आधुनिक होगी यातायात सुविधा

207 नवीन बसों का संचालन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल से राज्य पथ परिवहन निगम की 207 नवीन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नवीन बसों के संचालन से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सुदृढ़ होगी तथा आमजन को बेहतर यातायात सुविधा भी मिल सकेंगी। कार्यक्रम में श्री शर्मा ने नवीन बसों का विधिवत पूजन कर शुभारम्भ किया। इन बसों में आरएसआरटीसी की ओर से सर्विसलाइन पर ली गई 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस बसें, 79 स्टारलाइन बसें तथा 28 एसी वाहन की बसें शामिल हैं। बसों में नवीनतम सुरक्षा मानकों को उपयोग किया गया है, जिससे आमजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक यातायात सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 700 महिलाओं को सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में हेलमेट वितरित किए। ▪

विकास को जन आंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारम्भ किया। इसके अंतर्गत विकास की भावी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के स्तर पर विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च से 15 मई तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान के अंतर्गत 20 मार्च को ग्राम पंचायतों में पहली ग्राम सभा तथा सभी शहरी वार्डों में वार्ड सभा आयोजित की गई। जिसके माध्यम से अभियान की रूपरेखा के बारे में आमजन को अवगत कराया गया। इसके पश्चात चरणबद्ध रूप से अन्य ग्राम एवं वार्ड सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अंतर्गत पंचायत स्तरीय व वार्ड लेवल टीम द्वारा आमजन से चर्चा कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा तथा विभिन्न धारकों व विभागों से चर्चा उपरांत ग्राम सभा व वार्ड सभाओं में विकास के मास्टर प्लान के कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। अभियान में साक्ष्य आधारित योजना निर्माण पर जोर देते हुए हर गांव और शहरी वार्ड की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी डायनामिक प्रोफाइल एवं जीआईएस आधारित बेस मैप तैयार किए जाएंगे। अभियान के क्रियान्वयन के लिए पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जनआंदोलन की पहल है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर के वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। इसे आमजन के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया जाए।

प्रदेश में पहली बार प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हुई 2 लाख रुपये से अधिक

राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब के समग्र विकास को लेकर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने, लखपति दीदी योजना में लगभग 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है। इन प्रयासों से प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक हुई है।

स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास को मिलेगा मूर्त रूप

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत@ 2047 की संकल्पना की गई है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान@ 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाए जाने की घोषणा की। इसी क्रम में यह अभियान स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के रोडमैप को मूर्तरूप प्रदान करेगा। ■

लोक संस्कृति की मधुर बयार, अल्बर्ट हॉल में राजस्थान का श्रृंगार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राजस्थान दिवस पर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय स्थल पर भव्य राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, इसमें पद्मश्री अनवर खां मांगणियार और तगाराम भील सहित 100 से अधिक लोक कलाकारों व कथक नृत्यांगनाओं ने लोक गायन, घूमर, गैर, चरी, कच्छी घोड़ी व कालबेलिया जैसे नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। अंत में हुई रंग-बिरंगी आतिशबाजी और रोशनी से अल्बर्ट हॉल की भव्यता और बढ़ गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित भी किया। ▪

लोकतंत्र की नई धारा में जुड़ते गए रजवाड़े ...और बन गया आधुनिक राजस्थान

हरिओमसिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक

राजस्थान ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां के गौरवशाली इतिहास, परम्पराओं, स्थापत्य कला, स्मारकों, संस्कृति, खान-पान, पर्व एवं त्योहारों ने देशी-विदेशी पर्यटकों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है। यहां के कण-कण में स्वाभिमान एवं त्याग की भावनाएं, शौर्य एवं बलिदान की परम्परा रही है।

स्वतंत्रता से पूर्व, जहां राजस्थान की पहचान देशी रजवाड़ों की शानो-शौकत एवं शौर्य गाथाओं से थी, वहीं आज प्रदेश अनेक क्षेत्रों में देश-विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां के किले, महलों की दरो-दीवारें आज भी गौरवगाथाओं का बखान करती प्रतीत होती हैं। विभिन्न अंचलों में अलग-अलग बोलियां होने के बावजूद मिठास व अपनापन यहां की विशेषता रही है। यहां के तीज-त्योहारों और मेले-उत्सवों में संस्कृति एवं परम्पराओं का चलन आज भी जारी है। ऐतिहासिक धरोहर, थार के धोरे, बावड़ी व झीलों के साथ अभयारण्यों में वन्यजीवों की अठखेलियों को देखने प्रतिवर्ष लाखों देश-विदेश से पर्यटक राजस्थान भ्रमण पर आते हैं।

भारत के सबसे बड़े भू-भाग का गौरव होने के साथ ही इंदिरा गांधी नहरी तंत्र से खाद्यान्न उत्पादन, विपुल खनिज सम्पदा, पेट्रोलियम उत्पाद की खोज एवं रिफाइनरी की स्थापना की दिशा में बढ़ते कदम, सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बन रहे राजस्थान का भविष्य सुनहरा है। प्रदेश में जैतून की खेती, बीकानेर में जैतून रिफाइनरी, जयपुर में जैतून की चाय के उत्पादन ने विश्वभर में प्रदेश की अलग पहचान बनाने का कार्य किया है। औद्योगिक दृष्टि से भी राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होने के अलावा नीमराणा में जापानी औद्योगिक कॉरिडोर, बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना के साथ प्रत्येक तहसील वार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आरक्षित करने से अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश से होकर गुजर रहा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पूर्वी राजस्थान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना आने वाले समय में राजस्थान को समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ाने वाले कदम साबित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चहुंमुखी विकास को गति देते हुए प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन के लिए 'राइजिंग राजस्थान' जैसे आयोजनों में किये गए एमओयू को सफलतापूर्वक धरातल पर साकार किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना को गति दी जा रही है, सड़कों का तंत्र विकसित किया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के साथ घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है।

राजस्थान का एकीकरण - महत्त्वपूर्ण तथ्य

राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, अर्थात कुल 3144 दिन लगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देसी रियासतों को आत्म निर्णय का अधिकार दिया गया था। एकीकरण के लिए 5 जुलाई, 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वी.पी.मेनन थे। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए दो शर्त रखी गईं। प्रथम जनसंख्या 10 लाख से

अधिक होनी चाहिए, दूसरा वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। तत्कालीन समय में इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देशी रियासतों एवं तीन ठिकानों में विभक्त था। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया वर्ष 1948 से आरंभ होकर वर्ष 1956 तक सात चरणों में सम्पन्न हुई।

प्रथम चरण- मत्स्य संघ की स्थापना

सर्वप्रथम 27 फरवरी, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली रियासतों के एकीकरण से 18 मार्च, 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। इसकी राजधानी अलवर तथा उसके राजप्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह बनाए गए। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल करीब तीस हजार किलोमीटर था। जनसंख्या लगभग 19 लाख और सालाना आय एक करोड़ 83 लाख रुपये थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया, तभी विलय-पत्र में लिख दिया गया कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा।

द्वितीय चरण-पूर्वी राजस्थान का निर्माण

राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च, 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं शाहपुरा रियासतों को मिलाकर पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया गया। कोटा को इसकी राजधानी तथा कोटा के महाराव भीमसिंह को राजप्रमुख बनाया गया। इसका उद्घाटन भी तत्कालीन केन्द्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने छोटे भाई महाराव भीमसिंह की राजप्रमुखता में काम करना पड़े, मगर बड़े राज्य की वजह से भीमसिंह को राजप्रमुख बनाना तत्कालीन भारत सरकार की मजबूरी थी। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को मनाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राजप्रमुख बनाया जाएगा और बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीमसिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया।

तृतीय चरण-संयुक्त राजस्थान

राजस्थान के तीसरे चरण में पूर्वी राजस्थान के साथ उदयपुर रियासत को मिलाकर 18 अप्रैल, 1948 को नया नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, जिसकी राजधानी उदयपुर बनाई गई तथा मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख तथा कोटा के महाराव भीमसिंह को उपराजप्रमुख बनाया गया। श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में इसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को ही उदयपुर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया।

चतुर्थ चरण-वृहद राजस्थान

राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के चौथे चरण में 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा और जैसलमेर रियासतों के वृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए 30 मार्च, 1949 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया। इसकी राजधानी जयपुर तथा उदयपुर के महाराणा भूपालसिंह को महाराज प्रमुख, जयपुर के महाराजा मानसिंह को राजप्रमुख तथा कोटा के महाराव भीमसिंह को उपराजप्रमुख बनाया गया।

पंचम चरण-संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण

राजस्थान 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर देने से संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। नीमराना को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

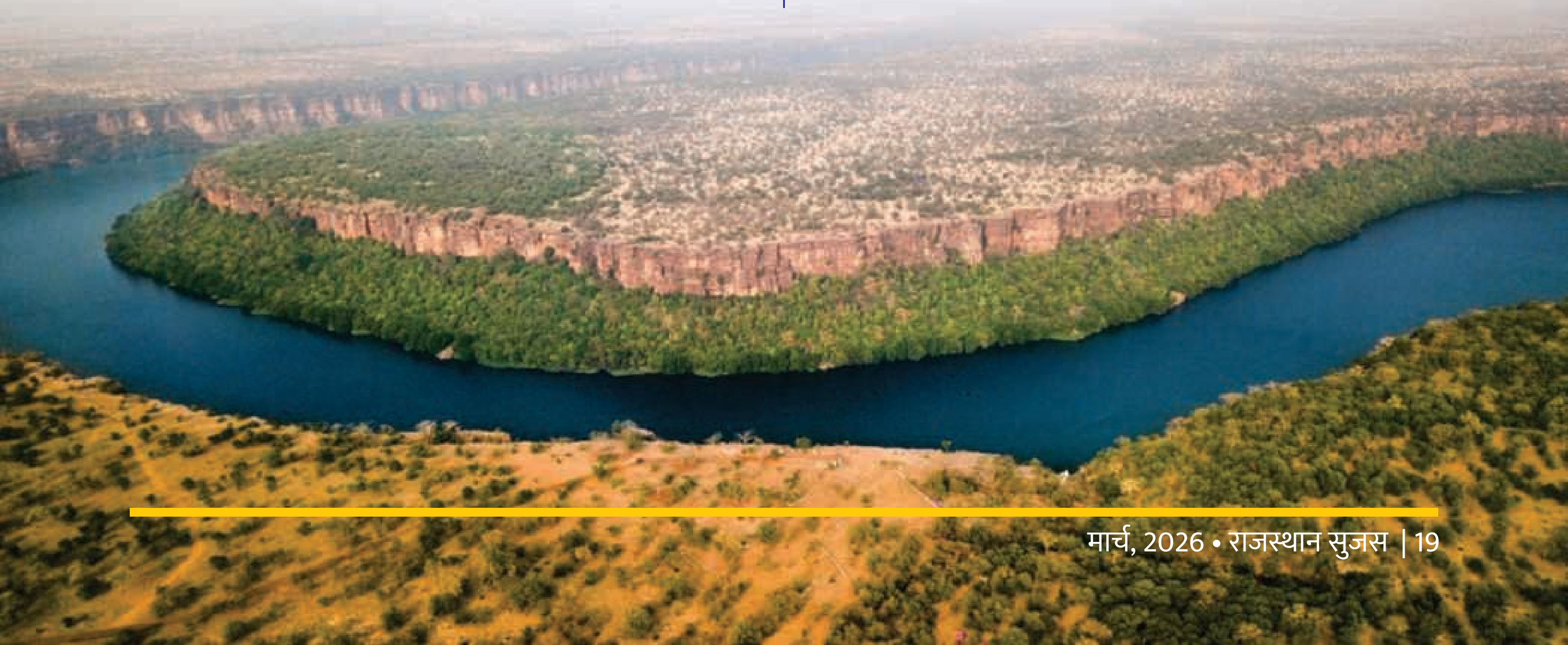

षष्ठम चरण-वर्तमान राजस्थान

राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का कामकाज दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी कौंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था। सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू-देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण आबू-देलवाड़ा तहसील को बंबई और शेष रियासतों के 26 जनवरी, 1950 को संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय हो जाने पर इसका नाम राजस्थान कर दिया गया।

सप्तम चरण-राज्य पुनर्गठन

राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिशों के आधार पर 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने से अजमेर-मेरवाड़ा, आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। इस चरण में कुछ भाग इधर-उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। इसके तहत मध्यप्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया और झालावाड़ जिले के सिरनौज को मध्यप्रदेश को दे दिया गया।

ऐतिहासिक तथ्य

जार्ज थॉमस ने सन् 1800 में राजस्थान के भू-भागों पर राजपूत राजाओं की सत्ता होने के कारण सर्वप्रथम 'राजपूताना' शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 1818 में अजमेर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तो उन्होंने राजपूताना की समस्त रियासतों पर अपना आधिपत्य कायम कर उन रियासतों को दो वर्गों; रियासत तथा ठिकानों में विभाजित किया। कर्नल टॉड ने वर्ष 1829 में अपनी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक 'एनाल्स एंड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान' में इस राज्य का नाम राजस्थान बताया, जो राजाओं के राज्य का प्रतीक था। ब्रिटिश शासकों ने राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से चार एजेंसियों में बांटा और प्रत्येक

रियासत में एक-एक रेजीडेन्ट तथा अजमेर में पॉलिटिकल एजेन्ट नियुक्त किया। 23 जून 1947 को भारत स्वातंत्र्य कानून से देशी रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान के साथ मिलाने की छूट दी गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर तथा अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर, स्वतंत्र रहने का निर्णय किया, जबकि उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर रियासतों ने भारत संघ के साथ मिलने का निर्णय लिया।

राजपूताना के नरेशों ने तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की चतुराई एवं दूरदर्शिता से भारत संघ में मिलना स्वीकार किया। तत्कालीन राजपूताना की 19 रियासतों एवं तीन चीफशिप (ठिकानों) वाले क्षेत्रों को विभिन्न चरणों में एकीकृत कर चैत्र सुदी प्रतिपदा विक्रम सम्वत् 2006 (30 मार्च 1949) को राजस्थान का गठन किया गया। एकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया सात चरणों में सम्पन्न हुई। राजस्थान राज्य भौगोलिक आधार पर नौ क्षेत्रों में विभाजित है। जिनमें अजेयमेरू (अजमेर) हाड़ौती, ढूंढाड़, गोडवाड (गोरखार), शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मेवात हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा व ऊंट, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य गीत केसरिया बालम और राज्य मिठाई घेवर हैं। ■

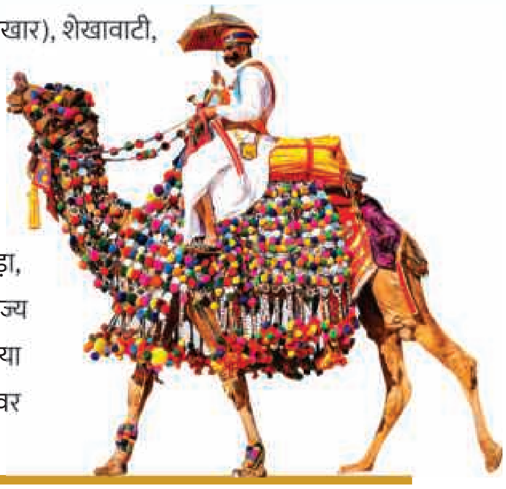

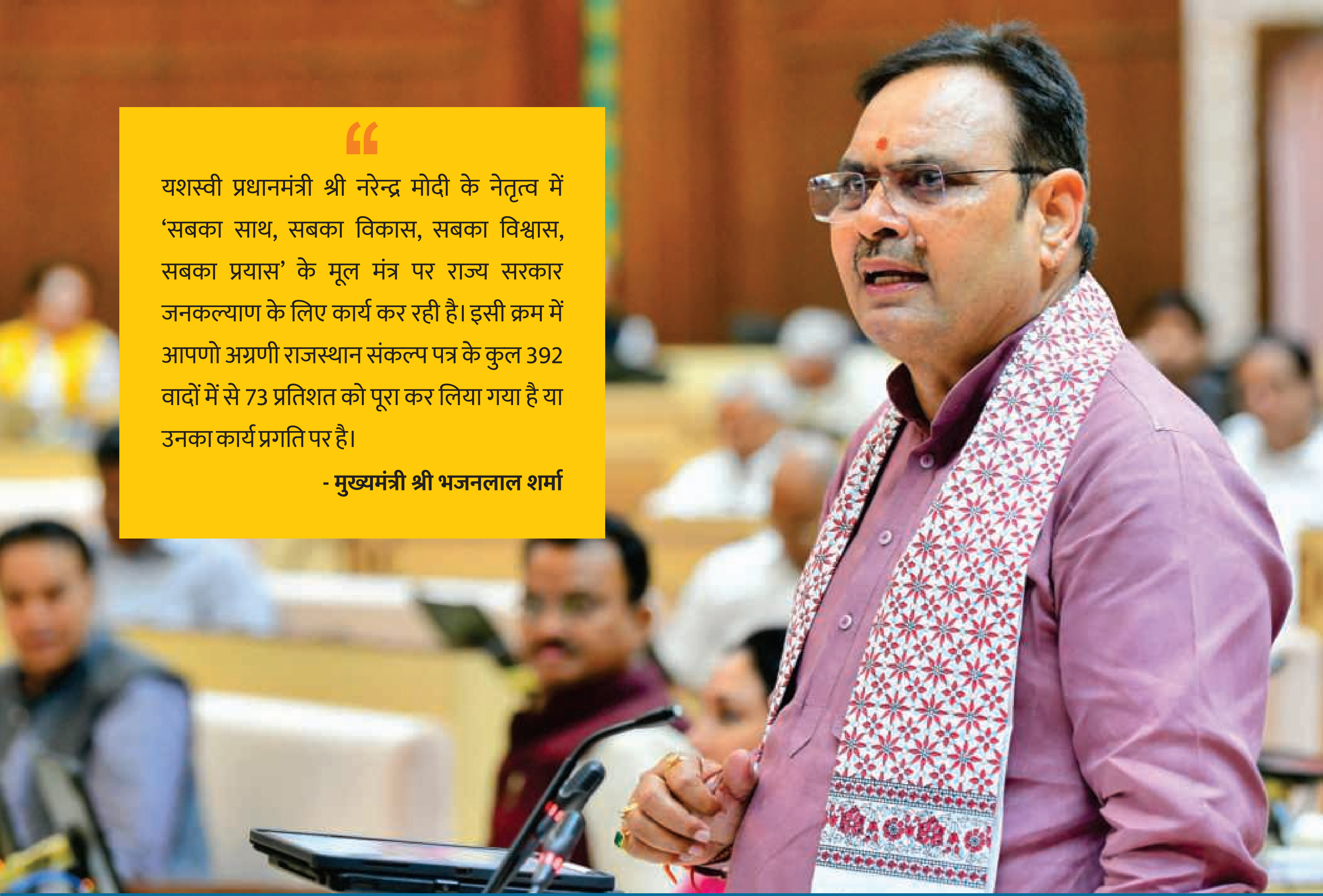

> “
> यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर राज्य सरकार जनकल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के कुल 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है या उनका कार्य प्रगति पर है।
>
> **- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

वित्त एवं विनियोग विधेयक पारित

नई पहलों-घोषणाओं से जन विश्वास और सुदृढ़

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत@2047 की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं विकसित राजस्थान @ 2047 के विज़न के साथ 11 फरवरी को विधानसभा में राज्य बजट 2026-27 पेश किया गया। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के उद्देश्य से घोषित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया।

इसी के साथ राज्य विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रस्तुत हैं बजट 2026–27 में घोषित विभिन्न नई पहल और घोषणाएं, जो राज्य के विकास के विविध आयामों को सशक्त बनाने के साथ-साथ जनविश्वास को और अधिक दृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगी।

ऊर्जा

- प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न GSS का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए एससी/एसटी काश्तकारों को ऐसी परियोजनाओं हेतु निःशुल्क भू-रूपान्तरण तहसीलदार के स्तर पर ही करने की व्यवस्था के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
- इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, अब नॉन एससी/एसटी श्रेणी के काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भू-रूपान्तरण, अप्रोच रोड के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी या सहायक आयुक्त, उपनिवेशन के स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी।
- राज्य में 33 केवी तक विद्युत कनेक्शनों हेतु स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा तथा संवेदनशील एवं

सार्वजनिक स्थलों पर ही विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण की अनिवार्यता होगी।

सड़क

- मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त का प्रावधान किए जाने की घोषणा।
- प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन सम्बन्धी कार्य 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित।

नागरिक सुविधाएं

- जयपुर में 42.80 किलोमीटर लम्बाई एवं 13 हजार 600 करोड़ रुपये लागत की जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण परियोजना के कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किए जाएंगे।
- द्रव्यवती नदी के ऊपर लगभग 36 किलोमीटर लम्बी ऐलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई जाकर निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोगों को आसानी से घर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' की समीक्षा कर नवीन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाई जाएगी।
- अन्य राज्यों की TDR Policies का अध्ययन कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नवीन TDR Policy लाई जाएगी।
- राज्य के प्रमुख शहरों में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन सीढ़ी की ऊंचाई तक भवन की ऊंचाई अनुमत करने के स्थान पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रावधान रखते हुए निर्माण करने पर भवन विनियमों के अनुसार देय ऊंचाई अनुमत की जाएगी।
- संभाग मुख्यालयों एवं अन्य बड़े शहरों यथा-भीलवाड़ा, अलवर आदि में सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष, 20 टाउन प्लानिंग योजनायें लाई जानी प्रस्तावित हैं।
- शहरी क्षेत्रों के लिए उपनगरीय सेवाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अन्तिम छोर तक पहुंच बेहतर किए जाने के उद्देश्य से एक हजार नए परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही, रोडवेज हेतु 300 नवीन बसें क्रय की जाएंगी।
- भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के सहयोग से 150 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं।
- आमजन को स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप सशक्त करने के साथ ही आगामी वर्ष 9 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा।

औद्योगिक विकास

- पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसका 91 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर यहां पर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग-टेस्टिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यहां एनसिलरी यूनिट्स विकसित करने के लिए राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया गया है। रिफाइनरी तथा इसकी एनसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु बालोतरा जिले में कौशल विकास हब विकसित किए जाने की घोषणा।
- औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा हेतु आगामी वर्ष 200 करोड़ रुपये तथा प्रकाश व्यवस्था, बिजली के तारों की शिफ्टिंग व भूमिगत करने के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- सरकार द्वारा नियोजित ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, जिनका विकास, रखरखाव एवं नियंत्रण अभी तक रीको को हस्तान्तरित नहीं किया गया है, उन्हें बेहतर प्रबन्धन के लिए रीको को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से RIPS-2019 के अन्तर्गत ऐसे प्रोजेक्ट, जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, किन्तु अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है, उनके लिए लाभ लेने की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है।

- राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2024 के अन्तर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जानी प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन राज्य में ही प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत सोलर सेल एवं मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को RIPS-2024 के तहत देय लाभों में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्षेत्र में निवेश को और प्रोत्साहित करने के लिए अब, केवल मॉड्यूल बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी RIPS के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं समावेशी बनाए जाने के लिए समग्र विकास, रोजगार सुरक्षा तथा आजीविका संवर्द्धन आवश्यक है। विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का कन्वर्जेन्स करते हुए इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, दोहराव की सम्भावना रोकने व गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा "विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)- वीबी-जी राम जी" योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाते हुए 125 दिनों की रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया गया है।
- श्रमिकों को जहां पहले 15 दिन में भुगतान किया जाता था, वहीं अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है।

“

राज्य सरकार शानदार काम करते हुए नीतिगत विकास और योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। राज्य सरकार के मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं की गईं, जिनमें से 919 घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और 1 हजार 531 पर कार्य प्रगतिरत है।

-मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

- निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते तथा नियोजित श्रमिक को मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आगामी वर्ष 4 हजार करोड़ रुपये का व्यय राज्य कोष से किया जाएगा, जिसे आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
- राज्य सरकार नागरिकों को समावेशी सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा/एकल नारी व लघु सीमान्त कृषकों को देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष 150 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए एक हजार 450 रुपये मासिक तक किए जाने की घोषणा।
- राज्य सरकार सभी वंचित वर्गों को सम्बल देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष दिव्यांगजन को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से 25 हजार दिव्यांगजन को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही, 2 हजार 500 दिव्यांगजन को निःशुल्क स्कूटी दिए जाने की घोषणा।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित

'हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना' के अन्तर्गत देय सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि सावधि जमा में विनियोजित की जाती है। अब इसके स्थान पर एकमुश्त राशि का भुगतान निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खाते में किया जाना प्रस्तावित है तथा पूर्व लम्बित प्रकरणों का निस्तारण भी इसी प्रकार किया जाएगा।

- प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास खोले जाएंगे।

युवा विकास एवं कल्याण

राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य एवं रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में-

- जहां सरकारी क्षेत्र में एक लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं।
- वर्तमान में एक लाख 43 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही, वर्ष 2026 में एक लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेण्डर भी जारी कर दिया गया है। आगामी वर्ष हेतु एक लाख पदों के स्थान पर एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती के लिए कैलेण्डर जारी किए जाने की घोषणा।
- युवाओं के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेन्टर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की स्थापना 450 करोड़ रुपये की लागत से की जानी प्रस्तावित।
- प्रदेश में स्कूली एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारम्भ करने तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे।
- प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुविधा सुलभ हो सके, इसके लिए विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत व भवन पुनर्निर्माण के साथ-साथ आधारभूत संरचना सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए 2 हजार

करोड़ रुपये की राशि से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाए जाने की घोषणा।

- प्रदेश में खेल स्टेडियम व अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

जनजाति कल्याण

- वनों में निवास करने वाले जनजाति भाईयों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार के अधिकार पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, इन वनाधिकार पट्टों की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनजाति भाईयों को ऐसी भूमि पर किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न योजनाओं तथा बैंकों से ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।
- फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्त्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत 8 लाख 50 हजार जनजाति कृषकों को 85 करोड़ रुपये का व्यय किया जाकर निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- जनजाति क्षेत्र के युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वनिधि योजना अन्तर्गत उन्हें चिन्हित कर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, आगामी वर्ष में जनजाति क्षेत्र के 5 हजार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जनजाति क्षेत्र के आस्था स्थलों-सोनार माता मंदिर-सलूम्बर, सलाकेश्वर महादेव मंदिर (आनंदपुरी) - बांसवाड़ा तथा रामकुण्डा महादेव मंदिर, पीलक (झाड़ोल) - उदयपुर में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- अपने प्रेरणा एवं श्रद्धा स्रोतों की स्मृति को जीवंत किए जाने की दृष्टि से झालामण्ड-जोधपुर में श्रीयादे पेनोरमा तथा नागाणा-बालोतरा में नागणेचिया माता पेनोरमा बनाए जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्यों तथा अन्य सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित।

कृषि एवं पशुपालन

- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित।
- आगामी वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देते हुए 2 हजार 735 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद की व्यवस्था किए जाने की घोषणा।
- कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की दृष्टि से कृषि विपणन के खण्डों का पुनर्गठन करते हुए पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बारां में खण्ड कार्यालय खोले जाएंगे।
- मार्केटिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धनिये के व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने तथा मार्केट लिंकेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मण्डी शुल्क की दर को 1.60 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत तथा आढ़त की दर 2.25 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे तथा डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
- गो सेवा और गो कल्याण को और अधिक गति देने के लिए गो सेवा नीति, 2026 लाने की घोषणा।

सुशासन

- प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन के साथ-साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
- विधानसभा सभागार के ऊपरी हॉल को ऑडिटोरियम बनाने, संग्रहालय के उन्नयन तथा डिजिटल स्क्रीन की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपये का व्यय किए जाने की घोषणा।
- विधानसभा के गठन की 75वीं वर्षगांठ के क्रम में इस वर्ष अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपये का व्यय करने की घोषणा।
- आगामी वर्ष एक हजार अतिरिक्त अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना किए जाने की घोषणा।
- विकसित राजस्थान @2047 के विज़न के अनुरूप योजनाबद्ध विकास किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोर्मेशन एण्ड इनोवेशन (RITI) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों से जिला स्तर तक के लिए विकास का मास्टर प्लान बनाए जाने की घोषणा।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवा पीढ़ी को नयी डिजिटल विधाओं में पारंगत करने के लिए ऑरेन्ज इकोनॉमी आधारित संस्कृति एवं सृजनशीलता के महत्त्व को रेखांकित किया है। देश में युवाओं को इस दिशा में अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों, इस दृष्टि से ऑरेन्ज इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- आज के युग में AI व मशीन लर्निंग की उपयोगिता से सभी भलिभांति परिचित हैं। किन्तु इनके स्मार्ट गवर्नेंस में उपयोग हेतु अत्यधिक डाटा के संधारण व प्रोसेसिंग की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से राज्य में AI एवं क्वांटम कम्प्यूटिंग मिशन प्रारम्भ किए जाने की घोषणा।
- प्रदेशवासियों के अमन चैन को सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अपराध नियंत्रण करने हेतु कड़ी एवं त्वरित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसी क्रम में व्यवस्था को और अधिक चाकचौबंद करने की दृष्टि से थानों एवं गश्ती दलों को डायल 112/100 से जोड़ते हुए इनके लिए चरणबद्ध रूप से एक हजार 250 वाहन तथा 2 हजार 500 नफरी उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित।

- महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम हेतु कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाना प्रस्तावित।
- पुलिस विभाग में तकनीकी संवर्ग में उच्च पदों की संख्या सीमित होने के कारण पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तकनीकी संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु काडर पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित।
- राज्य में महत्त्वपूर्ण भवनों एवं संस्थानों यथा-राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री आवास, हवाई अड्डों एवं औद्योगिक संस्थाओं यथा-रिफाइनरी आदि की सुरक्षा में नियोजित किए जाने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाना प्रस्तावित।
- पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते की राशि को 2 हजार 700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 हजार 850 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित।
- विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाएं 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जाने की घोषणा।
- प्रदेश में कानून के साथ-साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले / क्रमोन्नत किए जाएंगे।
- दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को 30 जून, 2016 से प्रभावी किए जाने की घोषणा।
- राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन कर सरकार को अभिशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया था। साथ ही, गत वर्षों में कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए अर्हता में 2 वर्ष तक की छूट दी गई थी। कतिपय कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस कारण, आगामी वर्ष आवश्यकतानुसार ऐसे कैडर में छूट देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड-डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा।
- पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मानदेय में आगामी वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित।
- राजकीय कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपलब्ध भूमि का समुचित विकास करते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से NBCC Pattern पर 3 हजार फ्लेट्स का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित।
- राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15 हजार रुपये को बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि 7 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की घोषणा।
- पत्रकार बन्धुओं के लिए राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से जयपुर में आवासीय योजना लायी जाना प्रस्तावित।
- समय-समय पर सम्मानित सदस्यों द्वारा किए गए आग्रह को ध्यान में रखते हुए राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से विधायक आवास योजना लाए जाने की घोषणा।
- विधायकगणों के वेतन में राज्य कर्मचारियों की भांति समय-समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी की जानी प्रस्तावित। यह प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की घोषणा।
- विधायकगणों को एक मोबाइल टैबलेट दिया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- कोटा एवं बूंदी जिले में 3-3 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के साथ ही, 3 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, क्रमोन्नयन, बैड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
- प्रदेश में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आगामी वर्ष आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत हेतु एक हजार 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा। ■

मा योजना

राजस्थान बना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उभरता मॉडल

अतर सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

सर्वे सन्तु निरामयाः

स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राज्य की आधारशिला होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश केवल व्यय नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य में किया गया निवेश है। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना का निरंतर विस्तार किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के संचालन, नियंत्रण और निगरानी का कार्य करती है। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ता निवेश

राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इसमें निवेश निरंतर बढ़ाया है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 27 हजार 69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। बढ़ते बजटीय निवेश के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है, अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है तथा आमजन को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, निरोगी राजस्थान योजना, चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन, नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास जैसे कार्यक्रम इसी व्यापक निवेश के माध्यम से प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सबके लिए

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक निवासी को आर्थिक बोझ से मुक्त उपचार उपलब्ध कराते हुए "स्वास्थ्य सबके लिए" के लक्ष्य को साकार करना है। वर्तमान समय में यह योजना राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से आमजन को सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे महंगे उपचार के कारण होने वाले आर्थिक संकट से परिवारों को राहत मिल रही है।

योजना का उद्देश्य -आर्थिक सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवा

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को महंगे उपचार के आर्थिक बोझ से बचाते हुए उन्हें सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने, गंभीर

बीमारियों के उपचार में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी वर्गों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही यह योजना राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अवधारणा को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं लागू हैं—पहली व्यवस्था बीमा मोड के रूप में है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये तक के उपचार का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मोड के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर लाभार्थियों को कुल 25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होती है। योजना की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अस्पताल में भर्ती होने के पांच दिन पूर्व तथा पंद्रह दिन पश्चात तक के उपचार खर्च को भी कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को उपचार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलती है।

उपचार पैकेज और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों और सर्जरी के लिए 2,179 उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं। इनमें 2,002 पैकेज बीमा मोड तथा 177 पैकेज ट्रस्ट मोड के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। समय के साथ योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष तथा जेरियाट्रिक अर्थात बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त योजना में अंग प्रत्यारोपण तथा कोक्लियर इम्प्लांट जैसे विशेष उपचार भी शामिल किए गए हैं। राज्य बजट की घोषणा के अनुसार कैंसर उपचार के 73 डे-केयर पैकेज भी योजना में सम्मिलित किए गए हैं, जिससे गंभीर रोगों के उपचार को अधिक सुलभ बनाया जा सके।

देशभर में उपचार की सुविधा - राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार

राजस्थान सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित किया है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत देश के 30,721 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इनमें लगभग 16,113 सरकारी अस्पताल और 14,608 निजी अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रमुख अस्पताल भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी -कहीं भी उपचार की सुविधा

योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी सुविधा है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को राज्य के बाहर भी उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 18 अप्रैल 2025 से लागू इनबाउंड पोर्टेबिलिटी के तहत अन्य राज्यों के पात्र लाभार्थी राजस्थान के सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 19 दिसम्बर 2025 से लागू आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राजस्थान के 1.36 करोड़ लाभार्थी परिवार राज्य से बाहर भी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था से गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले मरीजों को भी आर्थिक राहत मिल रही है।

लाभार्थी पात्रता

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कई सामाजिक और आर्थिक वर्गों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवार, सामाजिक-आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 में चिन्हित परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक तथा राज्य सरकार द्वारा चिन्हित अन्य वंचित और निराश्रित परिवार शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने बजट 2026–27 में इसके अतिरिक्त ऐसे असहाय, विमुक्त और लावारिस रोगी, जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

अपात्र परिवारों के लिए भी अवसर

जो परिवार स्वाभाविक रूप से योजना के पात्र नहीं हैं, वे भी वार्षिक प्रीमियम जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए परिवार को केवल 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा करना होता है, जबकि शेष 1,520 रुपये का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार कुल 2,370 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के प्रीमियम के साथ योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

मा योजना का संचालन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के संचालन, नियंत्रण और निगरानी का कार्य करती है।

योजना प्रगति

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान में व्यापक स्तर पर लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। वर्तमान में 1.36 करोड़ परिवार योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि 2.86 करोड़ लक्षित लाभार्थियों के विरुद्ध लगभग 2.28 करोड़ व्यक्तियों की e-KYC पूर्ण की जा चुकी है। यह प्रगति दर्शाती है कि योजना राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव छोड़ रही है और आमजन तक इसके लाभ तेजी से पहुंच रहे हैं। इससे राज्य में सबके लिए स्वास्थ्य अवधारणा प्रभावपूर्ण तरीके से फलीभूत हो रही है।

बजट 2026–27 की घोषणाएं

राजस्थान सरकार ने बजट 2026–27 में इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, मानसिक स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल रोगों की जांच, तथा गैर-संक्रामक रोग की स्क्रीनिंग और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे असहाय, विमुक्त और लावारिस रोगी, जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें भी मा योजना और निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। ■

प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की नई पहल

शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और रोजगार महिला सशक्तीकरण के आधार

वंजुल सांखला, स्वतंत्र लेखिका

हनुमानगढ़ की धान मंडी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल लॉन्च किया। लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण के प्रतीकात्मक चैक भी सौंपे। साथिन मार्गदर्शिका का डिजिटल लॉन्च और पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रदर्शनी और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

महिलाएं समाज की वह धुरी हैं, जिनके सशक्त होने से ही समाज प्रगति और देश विकास करता है। नारी शक्ति हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं, पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना, मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर, मनु भाकर, अवनी लेखरा ने विश्वभर में खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर किया नीतियों का निर्माण

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर नीतियों का निर्माण किया है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करवाया है। उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 70 प्रतिशत से अधिक घर महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर होने से तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से महिला उत्थान और सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्रदेश में बनी 16 लाख से अधिक लखपति दीदी

राज्य सरकार आधी आबादी के सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य में 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। वहीं, 1 लाख 39 हजार स्वयं सहायता समूहों को 679 करोड़ रुपये की आजीविका सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक महिला पेंशनरों को 6 हजार 876 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 27 हजार से अधिक कन्याओं के विवाह के लिए लगभग 101 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

6 लाख से अधिक बालिकाएं लाडो प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में लाडो प्रोत्साहन योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। योजना के अन्तर्गत सात किस्तों में डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जा रही है। जिससे अब तक 6 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मा वाउचर योजना सहित विभिन्न योजनाएं भी महिला कल्याण में सशक्त भूमिका निभा रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों के फलस्वरूप महिला अत्याचार के प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण करने का औसत समय वर्ष 2020 के 128 दिन से घटकर 52 दिन रह गया है। वहीं, राज्य में वर्ष 2023 की तुलना में महिला अत्याचार के प्रकरणों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आयी है।

योजनाओं, अवसरों और सुरक्षा से बदलती तस्वीर

राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए कृतसंकल्पित होकर अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। जिससे महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और आर्थिक विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें....

लाडो प्रोत्साहन योजना

राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रूप से लागू है। इस योजना के तहत बालिका को जन्म से लेकर शिक्षा तक 7 चरणों में (जन्म, पूर्ण टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 12 और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर) कुल 1.50 लाख रुपये की राशि DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब तक 6 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना

इस योजना के तहत ऐसी बालिकाओं और महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं, जो पारिवारिक या अन्य कारणों से नियमित रूप से कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती हैं। राज्य सरकार उन्हें दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस मोड) के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने के लिए संस्थान में जमा कराई गई फीस का पुनर्भरण प्रदान करती है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित न हो।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत महिलाओं एवं किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से RKCL के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें RS-CIT, RS-CFA (GST एवं Tally आधारित वित्तीय लेखांकन) और RS-CSEP जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो महिलाओं की रोजगार क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान सरकार की यह प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं, जिनकी वार्षिक आय 48 हजार रुपये से कम है, को आयु के आधार पर अधिकतम 1,500 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देकर उनके सम्मानजनक जीवनयापन में सहायक बनती है।

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना

यह योजना दूसरी संतान हेतु गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग और पोषण परामर्श पर आधारित है। योजनान्तर्गत लड़की के जन्म पर 8 हजार रुपये तथा लड़के के जन्म पर 6 हजार रूपये की सहयोग राशि सीधे उनके खातों में जमा की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी बार गर्भवती हुई महिला की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार कर, जन्म के समय शिशुओं में कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है।

MAA वाउचर योजना (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना)

राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना के तहत 12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर QR-आधारित ई-वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कन्या के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों को 31 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि अन्य बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारियों, विशेष योग्यजनों, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त, कन्या के दसवीं उत्तीर्ण होने पर 10 हजार रुपये और स्नातक होने पर 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, यह राशि 51 हजार रुपये तक हो सकती है। ▪

योजनाओं और नवाचारों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

8 मार्च महिला दिवस पर विशेष

सशक्त नारी विकास की आधारशिला

पूनम खंडेलवाल, सहायक निदेशक

किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक पैमाना वहां की महिलाओं की स्थिति से तय होता है। जब महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तब परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों मजबूत बनते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तीकरण को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनसे आधी आबादी की भागीदारी विकास की मुख्यधारा में और मजबूत हो सके। राज्य बजट में भी महिलाओं के लिए कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें रूरल विमेन बीपीओ की स्थापना, राज सखी स्टोर, अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, किशोरी बालिका योजना का विस्तार और मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना की सीमा में वृद्धि जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

लखपति दीदी और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 16 लाख से अधिक महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी हैं। यह उपलब्धि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेत है।

महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ स्थापित करने जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

राजीविका के माध्यम से नवाचार और नए उद्यम

राज्य सरकार राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नवाचार कर रही है। बजट घोषणा के अनुसार राजीविका के अंतर्गत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को कार्यालय और अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर महिला स्टार्टअप एन्टरप्रन्योर, रेडियो जॉकी, सरकारी विभागों में कार्यरत महिला अधिकारियों, आरएएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित छात्राओं, लखपति दीदी, समाजसेवी महिलाओं, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास पर कार्यरत महिला सुरक्षाकर्मियों एवं महिला कर्मचारियों से संवाद किया।

इन कार्यालयों में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के लिए "सक्षम सेंटर" भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को आधुनिक वित्तीय प्रणाली और डिजिटल तकनीकों की जानकारी मिल सके।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवियर, मिलेट्स और मसालों से जुड़े 50 नए एंटरप्राइजेज स्थापित किए जाएंगे। इन उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग और पैकेजिंग कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी जोड़ा जाएगा।

राज सखी स्टोर और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर्स स्थापित किए जाएंगे, जहां राजीविका से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों को बिक्री के बेहतर अवसर मिलेंगे।इसके साथ ही जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित किए जाएंगे, ताकि महिलाओं को उद्यम प्रबंधन और कौशल विकास का प्रशिक्षण मिल सके।

महिला उद्यमों को और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है। वहीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर "बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी" बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और महिलाओं की वित्तीय भागीदारी मजबूत होगी।

पोषण, स्वास्थ्य और बाल विकास पर विशेष ध्यान

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। इन वाटिकाओं से आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा तथा एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किशोरी बालिका योजना का विस्तार भी किया गया है। पहले यह योजना करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही जैसे आकांक्षी जिलों में संचालित थी, अब इसे राज्य के सभी 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित होंगी।

इसके अतिरिक्त, राजकीय कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की सुविधा के लिए 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल हेतु "मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन" भी चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे।

महिला सुरक्षा को मजबूत आधार

महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 की जाएगी। इसके साथ ही 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किए जाएंगे। पर्यटन स्थलों पर महिलाओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला सुरक्षाकर्मियों और गाइड्स की नियुक्ति कर पर्यटन सहायता बल को भी मजबूत किया जाएगा।

योजनाओं में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी

राज्य सरकार महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, सोलर दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बना रही है। इन योजनाओं से लाभान्वित होकर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है।

सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रदेश के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगी। ■

AI कर रहा चेहरे की पहचान

खुल रही डमी कैंडिडेट एवं अन्य अपराधियों की जन्मकुंडली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में राजस्थान के नवाचार बन रहे मिसाल

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम कर रहा है शासन एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बड़ी सहायता

एआई एप्लिकेशन से डमी कैंडिडेट, आदतन अपराधी और लावारिस शवों की पहचान का काम हो रहा आसान

जहां देश के दूसरे राज्य अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यात्रा की शुरुआत चैटबॉट-बेस्ड प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है। एआई-बेस्ड चैटबॉट सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद, राजस्थान सरकार ने अब एडवांस्ड कंप्यूटर विजन-आधारित एआई एप्लिकेशन को डिप्लॉय कर बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने जटिल फेस सिमिलैरिटी सर्च तकनीक में दक्षता प्राप्त कर इसे शासन एवं कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में लागू किया है, जिसके सुखद नतीजे सामने आने लगे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विकसित कंप्यूटर विजन-आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस सिमिलैरिटी सर्च समाधानों की सिरीज को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया गया है। यह अनूठी एआई प्रणाली प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रदायगी, कानून प्रवर्तन सहयोग तथा नागरिक सुरक्षा हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी के उपयोग की दिशा में महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है।

परीक्षा की शुचिता हो रही सुनिश्चित

प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों के बैठने-बिठाने की घटनाओं से संबंधित उभरती नवीन चुनौतियों के समाधान हेतु विभाग ने एआई-संचालित फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम विकसित किया है। इस एप्लिकेशन की मदद से संदिग्ध अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का पंजीकृत अभ्यर्थियों के 50 लाख रिकॉर्ड वाले मौजूदा डेटाबेस से मिलान संभव हो रहा है। उच्च-सटीकता वाले फेस सिमिलैरिटी मिलान के माध्यम से संभावित डमी कैंडिडेट के मामलों की पहचान करने में एजेंसियों को सफलता भी मिल चुकी है। यह एआई पहल सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं शुचिता को सुदृढ़ कर रही है तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान कर रही है।

लावारिस शवों की त्वरित पहचान

मानवीय एवं जनसेवा पहल के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने एक ऐसा फेस सिमिलैरिटी सर्च समाधान लागू किया है, जो लावारिस शवों की पहचान हेतु गुमशुदा व्यक्तियों, आपराधिक एवं अन्य डेटाबेस से मिलान करने में सहायता करता है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से अज्ञात शवों के फोटोग्राफ का गुमशुदा व्यक्तियों एवं अन्य इमेज डेटाबेस से मिलान किया जा सकता है। यह पहल सामाजिक प्रभाव एवं जनकल्याण हेतु एडवांस एआई तकनीक के संवेदनशील एवं मानवीय उपयोग को प्रदर्शित करती है।

आदतन अपराधियों की पहचान हो रही आसान

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कानून प्रवर्तन एवं अपराध अन्वेषण एजेंसियों की सहायता हेतु एक अन्य एआई-संचालित फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम भी डिप्लॉय किया गया है, जो प्रदेश में विभिन्न मामलों में आदतन अपराधियों की पहचान में सहायक हो रहा है। इसकी मदद से अभियुक्त की छवियों का 10 लाख फोटो युक्त रिकॉर्ड वाले आपराधिक डेटाबेस से मिलान किया जा सकता है। इससे अनेक अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान आसान हो रही है। यह एआई-संचालित प्रणाली एजेंसियों के लिए पैटर्न पहचान, आदतन अपराधियों की निगरानी एवं जांच में तीव्रता लाने में मददगार साबित हो रही है।

सुशासन एवं नवाचार में उपयोगी

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित ये सभी एआई एप्लिकेशन अत्याधुनिक एवं उच्च-सुरक्षित राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर में एयर-गैप्ड वातावरण में डिप्लॉय की गई हैं। साथ ही इनके ऑडिट लॉगिंग एवं ट्रेसबिलिटी, डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता सुरक्षा उपाय तथा नैतिक एवं उत्तरदायी एआई उपयोग को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नवाचार-प्रेरित परिवर्तन को आगे बढ़ाने तथा विभागों एवं एजेंसियों को स्केलेबल, सुरक्षित एवं प्रभावशाली डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ▪

राजस्थान अवसरों

हमारी सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। डबल इंजन सरकार राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। इन दो साल में राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। विकास के जिन वादों के साथ राजस्थान में डबल इंजन सरकार सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मोदी का अजमेर दौरा

बन रहा की भूमि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान के प्रति विशेष लगाव रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम प्रधानमंत्री जी के 'राजस्थान राइजिंग, रिलाएबल, रिसेप्टिव और रिफाइन' की अवधारणा को अपना ध्येय मान कर आगे बढ़ रहे हैं।

- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ

विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात

16 हजार 686 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी को राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में अजमेर से प्रदेशवासियों को 16 हजार 686 करोड़ रुपये की लागत के 43 प्रमुख कार्यों एवं परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण की सौगात दी। इसमें लगभग 8 हजार 554 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाएं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से तथा करीब 8 हजार 132 करोड़ रुपये की 9 प्रमुख परियोजनाएं केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा विभाग से जुड़ी हैं। इन विभागों में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं आवासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 4 हजार 516 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें लगभग 1 हजार 208 करोड़ रुपये की लागत से बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे व 1 हजार 114 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-वडोदरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 सेक्शन में एनएच 76 जंक्शन से एनएच 12 पर उम्मेदपुरा गांव तक 8 लेन कैरिजवे का लोकार्पण किया गया।

सड़क निर्माण कार्य

प्रदेशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण के लोकार्पण के विभिन्न कार्यों में 103 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर शाहपुरा से थानागाजी तक टू लेन सड़क, 546 करोड़ रुपये के देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा तक (चरण-एक) सड़क निर्माण कार्य, 190 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के (नया एनएच 58) अजमेर-नागौर सेक्शन के पेव शोल्डर के साथ टू लेन में अपग्रेडेशन एवं 110 करोड़ रुपये की लागत के जैसलमेर सम धनाना रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल है।

फोर लेन कार्य का शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जयपुर में 286 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पम्प होते हुए मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड, जोधपुर शहर में महामंदिर से आखलिया चौराहे तक 1 हजार 243 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन एलिवेटेड रोड, बारां जिले में 322 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के मालबमोरी-मांगरोल-बारां राज्य राजमार्ग एवं सवाईमाधोपुर में 111 करोड़ रुपये की लागत के एनएच 552 पर कुस्तला-सवाईमाधोपुर सेक्शन के फॉर लेन कार्य का शिलान्यास किया।

टीकाकरण के बाद प्रधानमंत्री ने किया बालिकाओं से संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कायड़ विश्रामस्थली में बने टीकाकरण स्थल से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने 9 से 14 वर्ष की पांच बालिकाओं को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीका लगाए जाने के बाद उनसे संवाद भी किया। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाला एक गंभीर रोग है। विश्व स्तर पर इसके लगभग 99 प्रतिशत से अधिक मामलों का मुख्य कारण एचपीवी संक्रमण है। टीकाकरण के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) में 526 करोड़ रुपये के आधारभूत संरचना और पेयजल आपूर्ति से संबंधित विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। इसी प्रकार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के लिए नोनेरा वृहद् पेयजल परियोजना के 1 हजार 21 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 4 पैकेज और परवन अकावद वृहद् पेयजल परियोजना के 2 हजार 247 करोड़ रुपये की लागत के 5 पैकेजों की एवं बीकानेर जिले के वृहद पेयजल परियोजना के 660 करोड़ रुपये के 2 कार्यों की आधारशिला रखी। बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, हनुमानगढ़ एवं डूंगरपुर जिले में नहरों के विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्यों का भी शिलान्यास किया।

पारेषण प्रणाली का लोकार्पण

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्रों से बिजली के सुगम पारेषण के लिए 3 हजार 616 करोड़ रुपये की पारेषण प्रणाली का लोकार्पण किया। साथ ही, 220 केवी के पांच और 400 केवी के दो ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) सहित 1781 करोड़ रुपये के विद्युत से जुड़े विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से दो युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र

इस अवसर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें 3 हजार 320 पटवारी (राजस्व), 2 हजार 291 संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक (ग्रामीण विकास), 2 हजार 590 पशुधन सहायक, 281 पशु परिचर, 3 हजार 822 सीएचओ, 472 फार्मा असिस्टेंट, 203 कम्पाउन्डर आयुर्वेद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 335, 7 हजार 357 पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, मेडिकल लैब तकनीशियन, लैब तकनीशियन, नर्सिंग प्रभारी, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, नर्स, नर्स ग्रेड-द्वितीय एवं खनन विभाग में विभिन्न पदों पर 101 सहित स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभागों की नियुक्तियां शामिल हैं।

विकास की राह पर राजस्थान बनेगा विकसित भारत की पहचान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अजमेर स्थित कायड़ विश्राम स्थली में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन से...

विकसित राजस्थान से विकसित भारत के मंत्र पर हम लगातार काम कर रहे हैं। विकास के जिन वादों के साथ राजस्थान में डबल इंजन सरकार सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है।

युवाशक्ति हो रही सशक्त

दो साल पहले तक राजस्थान में भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें आती रहती थीं। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में युवाशक्ति और सशक्त हो रही है।

महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं

एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ देश की नारीशक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। अगर मां स्वस्थ होती है, तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भावना से केन्द्र सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई हैं। गर्भावस्था के दौरान मां को पोषक आहार मिल सके इसके लिए बहनों के खाते में 5 हजार रुपये जमा करने की मातृ वंदना योजना शुरू की गई है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की गई है।

कनेक्टिविटी बढ़ने से राजस्थान में बढ़ रहे निवेश के अवसर

आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। अच्छी सड़क, रेल और हवाई सुविधा से सिर्फ सफर आसान नहीं होता, बल्कि पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल जाती है, इसलिए केंद्र सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन बढ़ता है। पर्यटक आते हैं, तो होटल, ढाबे, टैक्सी, गाइड आदि को काम मिलता है, राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है। कनेक्टिविटी बढ़ने से राजस्थान में निवेश के लिए अवसर भी बढ़ रहे हैं।

सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सिंचाई परियोजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना हो या यमुना-राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट, नदियों को जोड़ने के अभियान का राजस्थान को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती

राजस्थान अब सूरज की ताकत से समृद्धि कमाने वाली धरती बन रहा है। राजस्थान में धूप की कोई कमी नहीं और अब प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं से यही धूप आमजन के लिए बचत और कमाई का साधन बन रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सरकार लोगों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में दे रही है। प्रदेश में सवा लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और इस योजना की वजह से कई घरों का बिजली बिल अब लगभग जीरो आ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में अब तक 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत होकर विश्व मंच पर 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है। हाल ही में सम्पन्न हुई एआई समिट में पूरे विश्व ने देखा कि भारत भविष्य के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से भारत अब वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है।

प्रधानमंत्री का राजस्थान के प्रति विशेष लगाव

प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के प्रति विशेष लगाव रहा है। वे जब भी राजस्थान आए हैं, हमेशा प्रदेश को विकास की अनेक सौगातें देते हैं। उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के 'राजस्थान राइजिंग, रिलाएबल, रिसेप्टिव और रिफाइन' की अवधारणा को अपना ध्येय मान कर आगे बढ़ रही है।

युवाओं को 4 लाख भर्तियों के संकल्प की दिशा में ठोस कदम

राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को 4 लाख भर्तियों के संकल्प की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। अब तक सवा लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। 1 लाख 33 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। इन सभी निर्णयों से युवाओं में हमारी सरकार के प्रति विश्वास बहाल हुआ है।

कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत, 16 लाख से अधिक लखपति दीदी

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के सम्मान और सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदत्त 6 हजार की राशि में तीन हजार रुपये जोड़कर 9 हजार रुपये किया गया है। वर्ष 2026-27 के राज्य के कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कि राज्य की जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है। साथ ही, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। मा वाउचर योजना के माध्यम से सवा दो लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की गई है।

वीबी-जी राम जी के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक आवास तथा एनएफएसए में 72 लाख से अधिक नाम जोड़े गए हैं। वीबी-जी राम जी का राज्य में सभी सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। राज्य सरकार द्वारा भी बजट 2026-27 में इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भी विकसित राजस्थान @2047 का विजन दस्तावेज जारी किया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

लंबित जल विवादों के समाधान

हथिनी कुण्ड बैराज से यमुना का पानी लाने की परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र की जल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। वहीं, राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं से 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जल जीवन मिशन में भी राज्य सरकार ने गत दो साल में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन दिए हैं। साथ ही, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 4 लाख से अधिक भू जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

11 योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार प्रवर्तित योजनाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। देश की 11 योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर, 5 में दूसरे और 7 योजनाओं में तीसरे स्थान पर है। कुसुम कॉम्पोनेन्ट ए और सी में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर हैं। पीएम सूर्यघर योजना में भी राज्य सरकार ने 1 लाख 31 हजार रुफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का काम किया है। प्रदेश में अपराधों में औसतन 14 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भी 10 प्रतिशत की कमी आई है। गत 2 वर्षों में अब तक दर्जनभर से अधिक नीतियां लागू की गई हैं। साथ ही, राइजिंग राजस्थान में हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। ▪

बेटियों की स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर

बड़ा कदम

एचपीवी टीकाकरण से मजबूत होगा स्वस्थ भारत का सपना

तरुण कुमार जैन, उप निदेशक

एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। अगर मां स्वस्थ होती है, तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है।

-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौतियों में सर्वाइकल कैंसर एक प्रमुख समस्या रही है। इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी, 2026 को राजस्थान के अजमेर जिले से एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

सर्वाइकल कैंसर का कारण- एचपीवी संक्रमण और रोकथाम

यह अभियान न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बल्कि देश की करोड़ों बेटियों और महिलाओं के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की गारंटी देने वाला पावन संकल्प भी है। सर्वाइकल कैंसर, जो मुख्यतः एचपीवी संक्रमण के कारण होता है, महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे आम कैंसर है। विश्व स्तर पर लगभग 99 प्रतिशत मामलों में इस वायरस की भूमिका पाई गई है। ऐसे में इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण एक प्रभावी और वैज्ञानिक उपाय साबित हो रहा है।

सर्वाइकल कैंसर के बचाव- समय पर टीका, जीवनभर सुरक्षा

भारत के विभिन्न राज्यों में विषम भौगालिक परिस्थितियां होने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी जटिलताओं से भरी है। ऐसी स्थितियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया एक दूरदर्शी और संवेदनशील निर्णय है। यह अभियान विशेष रूप से 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि किशोरावस्था में ही इस घातक बीमारी से सुरक्षा प्रदान की जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार, एचपीवी टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। समय पर लगाया गया यह टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है।

हर जिले तक पहुंचती स्वास्थ्य पहल

राजस्थान में इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के पहले तीन महीनों के लिए प्रदेश में लगभग 1000 टीकाकरण केंद्रों की पहचान की गई है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति में टीके लगाए जा रहे हैं, साथ ही किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रथम चरण में राज्य को 3.65 लाख वैक्सीन डोज प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सभी जिलों में वितरित कर दिया गया है। अभियान के शुरुआती दिनों में ही उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है।

जागरूकता से बढ़ेगी भागीदारी

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही समाज में जागरूकता फैलाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। कई बार जानकारी के अभाव या भ्रांतियों के कारण लोग ऐसे टीकों से दूर रहते हैं, इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल का लाभ उठा सकें।

सशक्त पहल, सुरक्षित कल

एचपीवी टीकाकरण अभियान देश के स्वास्थ्य इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल बीमारी से बचाव का माध्यम है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। यह अभियान व्यापक जनसहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाने में सफलता मिलने की उम्मीद है। ■

राजस्थान स्थापना दिवस पर विशेष

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग

प्रकृति की शुभ दृष्टि पर अस्तित्व में आया हमारा प्रदेश

डॉ. अरुणा व्यास, स्वतंत्र लेखिका

राजस्थान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अस्तित्व में आया था। यह 30 मार्च 1949 का दिन था। इसके बाद आजाद भारत में एक परम्परा बन गई कि हर वर्ष 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गत वर्ष एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च अंग्रेजी तिथि पर मनाने की बजाय हिंदू पंचांग से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाये जाने की ऐतिहासिक पहल की। इस वर्ष राजस्थान का 77वां स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 19 मार्च को मनाया गया।

भारतीय पंचांग काल की वैज्ञानिक गणना पर आधारित एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। संस्कृति से जुड़े व्रत, त्योहार और शुभ कार्यों का निर्धारण इसी पंचाग से किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के संकेतक और मूल्य समाए हैं। पंचांग का शाब्दिक अर्थ है, पांच अंग वाला। यह पांच अंग हैं-वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। हिंदू काल गणना में कालदर्शन इन्हीं घटकों से होता है। इसका मूल प्रकृति है। प्रकृति में ही जीवन का सार-असार समाया है। वैसे भी यदि प्रकृति को ही समझ लिया तो फिर कुछ भी और समझने की जरूरत ही कहां रह जाती है!

भारतीय पंचांग काल के इसी प्रत्यक्ष दर्शन से जुड़ा है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण के मेल से बना यह पंचाग समय के शुभ-अशुभ प्रभाव की विरल दृष्टि है। हिंदू पंचांग में, महीने चंद्रमा की कलाओं यानी अमावस्या से पूर्णिमा के आधार पर गणित हैं। वर्ष की गणना सूर्य की गति के आधार पर की जाती है। पंचांग में तिथि नक्षत्र, योग, करण और वार जैसे पांच घटक चंद्र और सौर गति से जुड़े हैं। चंद्रमा पर प्रकाश और अंधेरे की अलग-अलग उपस्थिति अमावस्या-पूर्णिमा है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष इसी से जुड़े हैं। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक और शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक के दिनों को दर्शाता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कलाएं कम होने लगती हैं, इसलिए पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या के बाद चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं, इसलिए अमावस्या से पूर्णिमा तक के 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पुराण कथा के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति से श्राप मिला था, जिसके कारण उसे अपना तेज खोना पड़ा था। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा को अपना तेज वापस मिला और तभी से चंद्रमा की कलाओं के घटने-बढ़ने को दो पक्षों में बांटा गया। सनातन संस्कृति में कृष्ण पक्ष को शुभ कार्य के लिए अयोग्य माना जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष को शुभ कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। प्रकृति में पोषक तत्वों की कमी उसकी क्षीणता है, इसलिए कृष्ण पक्ष त्याज्य है। शुक्ल पक्ष प्रकृति में घुले तत्वों से पोषण के लिए अनुकूल होने के कारण वरणीय है।

यूरोपीय काल गणना संख्याओं की घटत-बढ़त है। वहां प्रकृति के पोषण, क्षीण तत्वों का विचार नहीं किया गया है। भारतीय पंचाग में तिथियां यह बताती हैं कि कौनसा दिन पोषक, मंगलकारी है। कौनसा दिन कुछ करने के लिए त्याज्य है। त्याज्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, बचकर चलना है। धूप, लू, ताप, अधिक सर्दी या फिर प्रकृति से जुड़े मारक दूसरे तत्वों से बचना भावी व्याधियों से मुक्ति ही तो है। प्रकाश और अंधकार या कहें, सूर्य-चन्द्र किरणों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से जोड़कर हमारे यहां काल-गणना को अभिव्यक्ति दी गयी है। प्रकृति के नियम विज्ञान से जुड़े हैं। विज्ञान अर्थात तथ्यों से जुड़ा ज्ञान। भारतीय संस्कृति में इसीलिए तथ्यों का अन्वेषण कर उससे जुड़ी दृष्टि हमने संजोई है। भारतीय पंचाग तथ्यों की इसी दृष्टि का समन्वय है।

राजस्थान प्रकृति की मांगलिक दृष्टि पर अस्तित्व में आया। तब भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग की शुभ घड़ी थी। पंचांग ने राजस्थान स्थापना के लिए इसीलिए वह दिन सुनिश्चित किया जो हमारे लिए ठीक था। दिवस मनाने की सार्थकता भी तो यही है कि वह हमारे भीतर उल्लास, उमंग जगाए। हमें विकास की ओर तेजी से ले जाने के लिए पुनर्नवा करे।

भारतीय पंचांग काल की वैज्ञानिक गणना पर आधारित एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। संस्कृति से जुड़े व्रत, त्योहार और शुभ कार्यों का निर्धारण इसी पंचाग से किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के संकेतक और मूल्य समाए हैं। पंचांग का शाब्दिक अर्थ है, पांच अंग वाला। यह पांच अंग हैं-वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। हिंदू काल गणना में कालदर्शन इन्हीं घटकों से होता है।

राजस्थान में अभावों में भी भाव संपन्नता की दृष्टि इसीलिए रही है कि यहां का इतिहास दिनांक रूपी संख्या की गणना में ही निहित नहीं रहा है, बल्कि उन मान्यताओं-परम्पराओं और विचारों से इसका नाता है जिसमें संस्कृति के गहरे सांस्कृतिक सरोकार समाए हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी यहां के लोगों ने कभी धीरज नहीं खोया। यहां की संस्कृति "सात वार और नौ त्योहार" से जुड़ी है। अभावों का रोना हमने कभी नहीं रोया। जो मिला, उसी से संतुष्टि पायी है। अभाव में भी भावों का हरा-समन्दर यहां मनाए जाने वाले तीज-त्योहारों में लहलहाता है।

यह राजस्थान ही है, जहां पर रेत के तपते धोरों से रंग-बिरंगी पगड़ी पहने अचानक कोई पुरुष रावण हत्थे पर संगीत की धुनें सुनाते पुरुषार्थ के गीत गाता नजर आता है, तो रंग-बिरंगी सजी चुनरी ओढ़े महिलाएं गांव-ढाणियों मे अभावों के बावजूद उत्सव के गीत गाती हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान का स्थापना दिवस यहां की सनातन संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष की थाती है। संस्कृति के सनातन मूल्यों का यह आलोक है। ▪

विकसित राजस्थान के संकल्प
को साकार करता बजट 2026-27

- डॉ. अरूण चतुर्वेदी
अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता राजस्थान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा **"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"** की सोच एवं विकसित राजस्थान की संकल्पना के साथ एक समावेशी बजट पेश किया गया तथा राज्य विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2026 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह बजट समाज के सभी वर्गों यथा युवा, किसान, महिला, मजदूर, गरीब, अपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े हर उस व्यक्ति के लिए है, जिसको सरकार की योजनाओं से अपेक्षाएं हैं।

राज्य बजट के आकार में 18 प्रतिशत वृद्धि

इस वर्ष राज्य का बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का है। यह बजट प्रदेशवासियों की खुशहाली, आमजन की जरूरतों एवं उनकी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया तथा प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने वाला है। राज्य सरकार "विकसित राजस्थान@2047" के विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग-धंधों तथा कृषि सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन पहलों से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

जनकल्याण एवं सुशासन की प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख नीतिगत निर्णय लेते समय **गरीब, युवा, अन्नदाता किसान एवं नारी** अर्थात **'GYAN'** हमेशा प्राथमिकताओं के केंद्र में रहने चाहिए। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास' के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश के समग्र विकास तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। बजट में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं एवं सेक्टोरल घोषणाओं के माध्यम से कृषि, शिक्षा, आधारभूत ढांचे, ऊर्जा तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे राज्य के युवा, महिलाएं, किसान एवं आमजन लाभान्वित होंगे।

महिला सशक्तीकरण - आधी आबादी की भागीदारी

प्रदेश की विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बजट में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत रूरल वूमेन बीपीओ की स्थापना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट सखी एवं बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित करना तथा महिला समूहों के माध्यम से अमृत पोषण वाटिकाओं के निर्माण जैसी पहलें की गई हैं। इन कदमों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण तथा ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन मिलने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण तथा निवेश आकर्षण

आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। विभिन्न प्रकार की सड़कों की मरम्मत, उन्नयन एवं निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों तथा प्रदेश के विद्युत तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जीएसएस के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बजट का विशेष फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, विशेष रूप से सोलर एवं विंड एनर्जी के विकास पर रखा गया है। 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों के प्रावधान के माध्यम से राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल होने के कारण ये पहल ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण तथा निवेश आकर्षण—तीनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन एवं युवा सशक्तीकरण

बजट 2026-27 में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने, एमएसएमई के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी विकसित करने, नए लॉजिस्टिक हब एवं औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। साथ ही युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में रोजगार, कौशल विकास एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संबंधी कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान तथा प्रत्येक जिले में स्किल डेवलपमेंट एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए VIBRANT, DREAM तथा i-Start Ambassador Program जैसे कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की पहल

प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के क्रमोन्नयन के साथ विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं डीबीटी अथवा ई-वाउचर के माध्यम से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। वहीं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के तहत आपातकालीन उपचार के लिए राज सुरक्षा योजना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु राज ममता योजना, जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना, जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में नए आईपीडी टावर का निर्माण तथा पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की घोषणा की गई है। इन पहलों से एक ओर शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आमजन को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य होने के कारण किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि अवसंरचना के विकास, सोलर पंपों की स्थापना, तारबंदी, ग्रीनहाउस जैसी योजनाओं तथा किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण पर ब्याज अनुदान से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही मंडियों में शेड एवं यार्ड सुविधाओं के विकास तथा डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इन पहलों से स्पष्ट है कि बजट में कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बजट में पर्यटन को रोजगार सृजन तथा स्थानीय विकास का प्रमुख माध्यम मानते हुए पर्यटन स्थलों के विकास, इको-टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन पहलों से राज्य के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी तथा पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ग्रीन पहल

आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण एवं समुचित संसाधनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीन बजट में भी वृद्धि की गई है। इस वर्ष ग्रीन बजट को 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आर्थिक प्रगति एवं वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2026–27 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था (जीडीपी) का आकार लगभग 21 लाख 52 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी प्रकार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है, जो पहले लगभग 1,67,000 रुपये थी। वहीं राजकोषीय घाटा राज्य की जीएसडीपी का मात्र 2.54 प्रतिशत रखा गया है। बुनियादी ढांचे पर बढ़ते निवेश के साथ वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमाओं में नियंत्रित रखना यह दर्शाता है कि राजस्थान वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ■

एमएसपी पर गेहूं खरीद
मजबूत हुआ किसानों का भरोसा

राजपाल लम्बोरिया, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की आय सुदृढ़ करने और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की व्यवस्था को सशक्त बनाया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस प्रदान कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी है। साथ ही, खरीदी गई उपज का भुगतान अधिकतम 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। दो वर्षों में राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से राहत मिली है और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है।

समर्थन मूल्य पर बोनस से मिला किसानों को लाभ

वर्ष 2024-25 में पूरे देश में लगभग 266 लाख मैट्रिक टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई। इसमें राजस्थान से 12.06 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। राजस्थान सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के उद्देश्य से इस पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया, जिससे किसानों को कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान मिला। इस निर्णय से प्रदेश के किसानों को कुल लगभग 150.66 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोनस राशि प्राप्त हुई। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिला।

वर्ष 2025-26 में खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

वर्ष 2025-26 में राजस्थान में गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष प्रदेश के 1 लाख 72 हजार 689 किसानों से कुल 21.37 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जिससे किसानों को कुल 2575 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिला। इस अतिरिक्त बोनस के रूप में प्रदेश के किसानों को कुल लगभग 320.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस पहल ने किसानों को बाजार भाव से बेहतर मूल्य उपलब्ध कराया और उनकी आय को स्थिरता प्रदान की।

हनुमानगढ़ का योगदान महत्त्वपूर्ण

रबी सीजन 2024 में राज्य में कुल 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद हुई, जिसमें लगभग 58 लाख क्विंटल गेहूं केवल हनुमानगढ़ जिले से खरीदा गया। यह राज्य की कुल खरीद का लगभग 48 प्रतिशत था और इस उपलब्धि के साथ हनुमानगढ़ जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। रबी सीजन 2025 में भी जिले ने अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी। इस वर्ष लगभग 46 हजार से अधिक किसानों से 86 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद की गई, जो राज्य में एमएसपी पर खरीदे गए गेहूं का लगभग 42 प्रतिशत है। इस खरीद के लिए किसानों को हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें लगभग 130 करोड़ रुपये बोनस राशि के रूप में शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में ही हनुमानगढ़ जिले के किसानों को गेहूं खरीद पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त बोनस सहायता प्राप्त हुई है।

समयबद्ध भुगतान से बढ़ा विश्वास

राजस्थान सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया है। गेहूं खरीद के बाद भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। अधिकतम 48 घंटे की समयसीमा तय की गई है, जबकि अधिकांश किसानों को 12 घंटे के भीतर ही भुगतान प्राप्त हो जाता है। इस व्यवस्था ने किसानों का भरोसा मजबूत किया है और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है।

मुख्यमंत्री का स्वागत गेहूं के गुलदस्ते से

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जब हनुमानगढ़ पहुंचे, तो किसानों ने उनका विशेष अभिनंदन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने गेहूं के

समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने तथा नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा को गेहूं का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच बैठकर उनसे सीधे संवाद किया।

श्री शर्मा ने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ देश की बड़ी आबादी के लिए अन्न उत्पादन करने वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं और राजस्थान को अनाज का कटोरा बनाने में यहां के किसानों का बड़ा योगदान है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए लक्ष्य

राजस्थान सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 23 लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ किसानों को कुल 2735 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। ■

परंपरा, पर्यटन और प्रगति का संगम

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

गजाधर भरत, सहायक निदेशक

भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र 'अतिथि देवो भव:' की भावना को आधुनिक स्वरूप देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अभिनव पहल की है। 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' के संकल्प के साथ प्रदेश में 'राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। यह योजना न केवल राजस्थान की पारंपरिक मेहमाननवाजी को वैश्विक मंच प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण आय और स्वरोजगार के नए आयाम भी स्थापित करने वाला एक सशक्त कदम साबित होगी।

सरलीकरण और डिजिटल सुशासन-डी-रेग्यूलेशन 2.0

इस योजना को भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप सरलीकृत किया गया है। यह योजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेन्द्रीकृत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने तथा छोटे स्तर के उद्यम को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर, मंजूरी को डिजिटल व तेज बनाया गया है। पहले जहां होमस्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और अधिक कागजी कार्यवाही करनी पड़ती थी अब सिंगल-विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

पर्यटन से समृद्धि- स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को नए पंख

राज्य में होमस्टे खोलना पहले की तुलना में अब अधिक सरल, तेज़ और किफ़ायती होगा, इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। अब गृहस्वामी होमस्टे इकाइयां अधिक सहजता से खोल और संचालित कर सकेंगे, जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा। ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और राज्य में पर्यटन और रोजगार को पंख लगेंगे।

नीतिगत सुधार और व्यावसायिक दक्षता

'राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026' के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम बैड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। इससे आवास क्षमता बढ़ेगी, लेकिन होमस्टे का पारिवारिक स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा और छोटे उद्यमियों को भी पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह योजना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पूर्व में लागू शर्त जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा को इस योजना में समाप्त कर दिया गया है। अब होमस्टे इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी, लीजधारी या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयरटेकर द्वारा किया जा सकेगा। यदि स्वामी या पट्टेदार स्वयं परिसर में निवास नहीं करता है, तो दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर नियुक्त किया जा सकेगा। इससे संचालन में लचीलापन और व्यावसायिक दक्षता दोनों सुनिश्चित होंगे।

सरल और पारदर्शी आवेदन संभव

योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे घर बैठे सरल और पारदर्शी आवेदन संभव होगा। आवेदन प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। तीन माह के भीतर निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिसकी वैधता दो वर्ष होगी। यदि निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गृहस्वामी अपने निकटतम पर्यटक स्वागत केन्द्र (TRC) के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी।

सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर सुविधा का वादा

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक होमस्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा। प्रत्येक किराये के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल एवं विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निकायों के अनुरूप कचरा निस्तारण की व्यवस्था भी आवश्यक होगी। प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना तथा अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम सात वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है। योजना के अंतर्गत होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और गोल्ड श्रेणी के लिए दो हजार रुपये निर्धारित है। गोल्ड श्रेणी में एसी/हीटिंग, इंटरनेट सुविधा, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। ▪

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था
- अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति
- स्वामी/परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त
- स्वामी, लीजधारी या नियुक्त केयरटेकर द्वारा संचालन संभव
- पूर्णतः ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी

पंजीकरण

- 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में स्थायी प्रमाणपत्र
- स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत पंजीकरण
- ग्रामीण पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

'वायु शक्ति-2026' अभ्यास का अवलोकन

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में 'वायु शक्ति-2026' अभ्यास का अवलोकन किया। वायु शक्ति अभ्यास में एक सुनियोजित परिचालन रणनीति का पालन किया गया, जिसमें वास्तविक, एकीकृत युद्ध क्षेत्र का अनुकरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह शामिल थे। वायु शक्ति-2026 अभ्यास में भारतीय वायु सेना के साहस, समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्धकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सटीक हमले करने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। इस अभ्यास में विभिन्न लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हमलावर हेलीकॉप्टरों ने निर्धारित लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाया। रेगिस्तान में विमानों की गर्जना और सटीक बमबारी ने भारतीय वायु सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता और परिचालन तत्परता का जीवंत प्रदर्शन किया। ■

डाक जीवन बीमा
भरोसे, सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा

मोहन सिंह मीना, प्रवर अधीक्षक डाकघर

**"उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥"**

अर्थ: केवल इच्छा करने से कार्य पूरे नहीं होते, बल्कि प्रयास और दूरदर्शिता से ही सफलता मिलती है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता।

यह श्लोक यह संदेश देता है कि जीवन में सुरक्षा और स्थिरता केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि समय रहते सही निर्णय लेने से मिलती है। भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था भी दूरदर्शिता का एक हिस्सा है।

बीमा का महत्व और आवश्यकता

बीमा आधुनिक जीवन की एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति से जुड़े संभावित जोखिमों के लिए सुरक्षा प्राप्त करता है। किसी भी अनिश्चित परिस्थिति में यह आर्थिक सहारा प्रदान करता है और परिवार को कठिन समय में स्थिरता देने में मदद करता है। इस योजना में बीमा धारक को कम प्रीमियम और अधिक बोनस का भुगतान किया जाता है।

डाक जीवन बीमा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में कई सरकारी और निजी बीमा संस्थाएं कार्यरत हैं, परंतु डाक विभाग द्वारा संचालित डाक जीवन बीमा का अपना विशेष महत्व है। इसकी शुरुआत वर्ष 1884 में की गई थी, जिससे यह देश की सबसे पुरानी जीवन बीमा सेवाओं में से एक बन गई। लंबे समय से यह योजना नागरिकों को विश्वसनीय बीमा सेवाएं प्रदान करती आ रही है और समय के साथ इसकी उपयोगिता और दायरा दोनों बढ़े हैं। योजना में 6 माह व 12 माह का अग्रिम प्रीमियम जमा कराने पर जमा प्रीमियम पर क्रमशः एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाती है।

सरल और भरोसेमंद दावा प्रक्रिया

डाक जीवन बीमा की एक प्रमुख विशेषता इसकी सरल और पारदर्शी दावा प्रक्रिया है। इसमें दावा निस्तारण के समय मृत्यु के कारण को आधार नहीं बनाया जाता। किसी भी प्रकार की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि के साथ अर्जित बोनस का भुगतान किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कठिन परिस्थितियों में बीमाधारक के परिवार को समय पर आर्थिक सहारा मिल सके।

समय के साथ बढ़ता दायरा

प्रारंभिक समय में डाक जीवन बीमा की सुविधा मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थी। बाद में इसकी पहुंच का विस्तार करते हुए इसे विभिन्न पेशों से जुड़े शिक्षित और पेशेवर लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था के माध्यम से बीमा सुविधा प्रदान की गई, ताकि समाज के अधिक से अधिक वर्गों तक आर्थिक सुरक्षा की यह व्यवस्था पहुंच सके।

सुलभ और उपयोगी योजना

डाक जीवन बीमा की योजनाएं जीवन के विभिन्न चरणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें जीवन सुरक्षा, बचत और भविष्य की योजना को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न माध्यमों से भुगतान कर सकें।

डाक जीवन बीमा प्रीमियम को विभिन्न माध्यमों से जमा करवाया जा सकता है जैसे- ऑनलाइन नेट बैंकिंग, नकद, सीधे बैंक खाते /डाकघर बचत खाते से NACH सुविधा, IPPB खाते द्वारा ऑनलाइन जमा सुविधा और डाक सेवा app के जरिये।

डाक जीवन बीमा केवल एक वित्तीय योजना नहीं है, बल्कि यह भारतीय डाक विभाग की सेवा भावना का भी प्रतीक है। "डाक सेवा – जन सेवा" के सिद्धांत पर आधारित यह योजना लंबे समय से नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। अपनी विश्वसनीयता, सरल व्यवस्था और व्यापक पहुंच के कारण आज भी अनेक लोगों के लिए सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण विकल्प बनी हुई है। ■

आवश्यक सूचना

फार्म-1
(नियम 3 देखिये)

1.	समाचार पत्रिका का नाम	:	राजस्थान सुजस
2.	समाचार पत्रिका की भाषा	:	हिन्दी
3.	प्रकाशन का स्थान	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
4.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
5.	मुद्रक का नाम	:	राकेश शर्मा
	क्या भाारतीय नागरिक हैं	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
6.	पता प्रेस	:	रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, 22 गोदाम, जयपुर मै. कृष्णा प्रिंटर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, रामनगर, जयपुर हाईटेक प्रिंटर्स, मालवीय नगर, जयपुर
7.	सम्पादक का नाम	:	रजनीश शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक है	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
	पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर

8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं, राकेश शर्मा एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

राकेश शर्मा

प्रदेश के बढ़ते कदम

लोकल से ग्लोबल समृद्धि की ओर...

शैलेन्द्र सिंह, राज. आर्थिक एवं सांख्यकी सेवा

निर्यात को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य को एक मजबूत निर्यातक राज्य बनाने के उद्देश्य से यह नीति लागू की है।

राजस्थान पारंपरिक रूप से हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और खनिज उत्पादों में मजबूत रहा है, लेकिन अब राज्य अपने निर्यात पोर्टफोलियो को विविध बनाकर नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल निर्यात लगभग 83 हजार 704 करोड़ रुपये रहा है और इस नीति के माध्यम से इसे वर्ष 2029 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यह नीति क्या है ?

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य सरकार की एक व्यापक रणनीति है, जिसका उद्देश्य राज्य के उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ना तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। यह नीति निर्यातकों को वित्तीय सहायता, अवसंरचना, बाजार संपर्क, तकनीकी समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करके एक सक्षम निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र (Export Ecosystem) तैयार करती है।

यह नीति दिसंबर 2024 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

नीति के उद्देश्य

- वर्ष 2029 तक निर्यात को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना
- लॉजिस्टिक्स, एयर कार्गो और निर्यात अवसंरचना को मजबूत करना
- उत्पाद विविधीकरण एवं नए बाजारों की खोज
- निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना
- अनुसंधान एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन
- कौशल विकास के माध्यम से निर्यात क्षेत्र में कार्यबल बढ़ाना
- निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

यह नीति राज्य के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जिनमें इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एवं ज्वेलरी, स्टोन एवं मिनरल, टेक्सटाइल एवं परिधान तथा हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग शामिल हैं। इसके साथ ही एग्री एवं फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी तथा हेल्थ एवं वेलनेस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी इसमें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है, जिससे राजस्थान की निर्यात क्षमता को विविध और सशक्त बनाया जा सके।

नीति की प्रमुख विशेषताएं

1. PUSH Framework

P – Promotes (प्रोत्साहन) • U – Upgrades (उन्नयन) • S – Streamline (सरलीकरण) • H – Harness (सशक्तीकरण) यह मॉडल निर्यात को बढ़ाने के लिए समग्र रणनीति प्रदान करता है।

2. लॉजिस्टिक्स एवं फ्रेट सब्सिडी

निर्यातकों की परिवहन लागत को कम करने के लिए नीति के अंतर्गत 25 प्रतिशत तक फ्रेट सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित है। इससे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिलती है।

3. मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग सहायता

राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत भागीदारी पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 3 लाख रुपये) प्रतिपूर्ति की जाती है, जिससे "Brand Rajasthan" को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।

4. गुणवत्ता एवं तकनीकी सहायता

निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रमाणन, परीक्षण एवं दस्तावेज़ीकरण पर सब्सिडी दी जाती है। साथ ही नई तकनीकों को अपनाने के लिए 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 50 लाख रुपये) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन सकें।

5. ई-कॉमर्स निर्यात प्रोत्साहन

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फीस पर 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 2 लाख रुपये) सहायता दी जाती है। इससे विशेष रूप से MSME इकाइयों को ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है।

6. बीमा एवं वित्तीय सहायता

निर्यातकों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से ECGC बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 2 लाख रुपये) सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है।

7. निर्यात विकास कोष

राज्य सरकार द्वारा एक विशेष निर्यात विकास कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उत्पाद विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय एक्सपो, व्यापार मेलों तथा Buyer-Seller Meets का आयोजन किया जाता है, जिससे निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है।

संस्थागत ढांचा

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचा विकसित किया है, जिसमें राज्य, जिला एवं कार्यान्वयन स्तर पर विभिन्न समितियों और इकाइयों की भूमिका निर्धारित की गई है।

- REPCC (Rajasthan Export Promotion Coordination Committee) **राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन समन्वय समिति-** यह राज्य स्तर की सर्वोच्च समिति है, जो नीति के समन्वय, मार्गदर्शन तथा रणनीतिक निर्णय लेने का कार्य करती है। यह विभिन्न विभागों के बीच तालमेल स्थापित कर निर्यात वृद्धि हेतु नीतिगत दिशा प्रदान करती है।
- REPC (Rajasthan Export Promotion Council) **राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद** यह परिषद, उद्योग और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करना, उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना है।
- DEPC (District Export Promotion Committee) **जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति-** यह जिला स्तर पर कार्य करने वाली समिति है, जो स्थानीय उद्योगों और निर्यातकों की पहचान, समस्याओं के समाधान तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। यह जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- PMU (Project Monitoring Unit) **परियोजना निगरानी इकाई-** यह इकाई नीति के कार्यान्वयन की सतत निगरानी, मूल्यांकन और प्रगति की समीक्षा करती है। PMU डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हो।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024 राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करते हुए निर्यात में वृद्धि, व्यापक रोजगार सृजन तथा एमएसएमई और कारीगरों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह नीति "लोकल टू ग्लोबल" की अवधारणा को सशक्त बनाते हुए राजस्थान के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके माध्यम से पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलती है और आधुनिक क्षेत्रों को वैश्विक अवसरों से जोड़कर संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024 केवल एक नीति नहीं, बल्कि "राइजिंग राजस्थान" और "विकसित राजस्थान @2047" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त रोडमैप है। यह नीति राजस्थान को एक प्रतिस्पर्धी, नवाचार-आधारित और समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का सशक्त आधार तैयार करती है-जहां निर्यात में वृद्धि ही विकास और समृद्धि की नई पहचान बनती है। ▪

एकाकार हुई शेखावाटी से लेकर

ब्रज तक की होली

Holi

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमजन के साथ होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्री शर्मा ने सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर होली पूजन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने यहां श्री राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में विधिवत् रूप से होली पूजन किया। इसके बाद मंत्रोच्चार के बीच होलिका दहन किया गया।

मुख्यमंत्री निवास पर हुए होली महोत्सव में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आए लोगों ने फूलों और प्राकृतिक रंगों के साथ यह त्योहार मनाया। श्री शर्मा ने आमजन को गुलाल लगाया और फूलों की वर्षा कर पूरी आत्मीयता के साथ सभी का अभिनन्दन किया। होली के पावन पर्व पर प्रदेशभर की संस्कृति एक छत के नीचे नजर आई, जब ब्रज से लेकर शेखावाटी तक की होली के विभिन्न रूप देखने को मिले। ब्रज से आए भारतीय कला संस्थान के कलाकारों एवं भजन मंडली ने गायन और नृत्य के साथ समां बांधा। वहीं, शेखावाटी के फतेहपुर की गो वत्स फाग मंडली के कलाकारों ने चंग के साथ धमाल मचाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कलाकारों के बीच जाकर फाल्गुन के गीतों में साथ निभाया। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हों या जवान सभी में मुख्यमंत्री के साथ होली खेलने को लेकर अलग ही उत्साह नजर आया। किसी ने मुख्यमंत्री को गुलाल लगाने के साथ साफा और दुपट्टा पहनाया, तो किसी ने अपने हाथों से बनी पिचकारी एवं गुलाल गोटा भेंट किया। ■

कृष्णमृगों की धरा-तालछापर

विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च)

मनीष कुमार, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

फोटो- उमेश बागोतिया, रेंजर, तालछापर वन्यजीव अभयारण्य

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन व खनन पर निर्भर करती है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में पक्षी व वन्यजीव विहार अग्रणी भूमिका निभाते हैं। चूरू का तालछापर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के महत्त्वपूर्ण पक्षी विहार स्थलों में से एक है। ताल छापर अभयारण्य अपनी जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों, खुली घासभूमि और विशेष रूप से कृष्ण मृगों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह अभयारण्य थार की मरु-भूमि के किनारे बसा है और अपने अनोखे पारिस्थितिक तंत्र के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाइल्डलाइफ प्रेमियों तथा शोधकर्ताओं के आकर्षण केंद्र बना हुआ है।

भारत में पहली बार जसवंतगढ़ में कृष्ण मृगों का किया ट्रांसलोकेशन

आज के युग में पारिस्थितिकी व पर्यावरण संतुलन के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समर्पित प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार के संकल्पित प्रयासों से तालछापर में काले हिरणों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए हाल ही ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य से निकटवर्ती जसवंतगढ़ वन क्षेत्र में हैबिटेट मैनेजमेंट एंड ग्रासलैंड डवलपमेंट हेतु 1.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि से 04 हैक्टेयर क्षेत्र में कृष्णमृग एनक्लोजर विकसित कर 22 कृष्णमृगों को ट्रांसलोकेट किया गया है। यह ट्रांसलोकेशन कार्य सम्पूर्ण भारत

में पहली बार है, जब वाइल्ड टू वाइल्ड ब्लैकबक ट्रांसलोकेट किए गए हैं। जसवंतगढ़ में ताल वेटलैंड विकसित होने और कृष्ण मृगों के स्थानांतरण से यहां जैव विविधता को नया जीवन मिला है। जसवंतगढ़ में वेटलैंड विकसित होने से प्रवासी पक्षियों की आवक भी बढ़ी है और हाल ही में सर्द ऋतु के दौरान यहां भरपूर संख्या में प्रवासी पक्षी देखे गए हैं।

ग्रासलेंड और कृष्ण मृगों के लिए मशहूर

ताल छापर अभयारण्य अपनी घास भूमि और कृष्ण मृगों के लिए मशहूर है। अभयारण्य चूरू जिले के सुजानगढ़ के छापर कस्बे में स्थित है और यह लगभग 719 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1998 में ताल छापर को पूर्णतया अभयारण्य का दर्जा दिया गया तथा इसे मुख्यतः ब्लैकबक (कृष्ण मृग) के संरक्षण के लिए संरक्षित किया गया। ताल छापर का मुख्य आकर्षण है ब्लैकबक या कृष्ण मृग, जो

अपने मोड़दार सींगों तथा तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। अभयारण्य में इन मृगों की अच्छी संख्या देखने को मिलती है, जो खुले मैदान में घूमते हुए पर्यटकों को प्राकृतिक रूप से आकर्षित करते हैं।

यहां की घास भूमि पर मोथिया घास पाई जाती है, जो कृष्ण मृगों के चारे के रूप में बेहतरीन है। इसी के साथ यहां का पानी खारा होने के कारण घास का स्वाद थोड़ा नमकीन होता है, जो इसे अन्य से अलग बनाता है। नमकीन स्वाद होने के कारण सामान्यतया इसे 'लूणिया घास' कहा जाने लगा है। यहां की जैव विविधता और कृष्णमृग पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। पिछले 3 वर्षों में यहां कुल 18785 पर्यटकों ने भ्रमण किया है। वर्ष 2023-24 में 5203 भारतीय, 958 विद्यार्थी व 112 विदेशी पर्यटक सहित कुल 6273 पर्यटक, वर्ष 2024-25 में 4416 भारतीय, 1232 विद्यार्थी व 124 विदेशी पर्यटक सहित कुल 5772 पर्यटक तथा वर्ष 2025-26 में जनवरी, 2026 माह तक 5284 भारतीय, 1381 विद्यार्थी व 75 विदेशी पर्यटक सहित कुल 6740 पर्यटकों ने तालछापर वन्यजीव अभयारण्य में भ्रमण किया है।

बढ़ी प्रवासी पक्षियों की आवक

ताल छापर अभयारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। वर्ष के सितंबर से मार्च तक यहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इस दौरान यहां साइबेरिया सहित दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से 300 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं। राजस्थान की संस्कृति का सजीव चित्राण प्रवासी पक्षी 'कुरजां' तालछापर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। कुरजां पक्षी कजाकिस्तान व मंगोलिया मूल के माने जाते हैं। राजस्थान की संस्कृति में 'कुरजां ए म्हारा भंवर मिला द्यो ए...' जैसे लोकगीतों में भी कुरजां पक्षियों को संदेशवाहक के रूप में बड़ा महत्व दिया गया है।

अभयारण्य में कृष्णमृगों के अलावा पक्षियों में ब्लैक शोल्डर्ड काईट, लेगर फाल्कन, रेड नेक्ड फाल्कन, इजिप्शन वल्चर, हिमालयन ग्रीफन वल्चर, यूरेशियन

ग्रीफन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, पैलेड हैरियर, मोंटेग्यू हैरियर, ब्लैक फ्रेंकोलिन, कॉमन कैस्टल, चेस्नेट बैलिड सैंड ग्राउज, व्हाइट ब्राउड फैंटेल, ब्राउन रॉकचैट, यूरेशियन कलर्ड डव, स्पॉटेड आऊलेट, इंडियन स्कोप्स ओवल, कॉमन कूट, लिटिल ग्रेब, नॉर्थन स्वाउलर, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक आदि पक्षी सामान्यतया देखे जा सकते हैं। इन पक्षियों के अलावा चिंकारा, नीलगाय, डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, जैकाल, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, खरगोश आदि वन्यजीव भी आसानी से दिखाई देते हैं।

यह क्षेत्र न सिर्फ घास का मैदान है, बल्कि यहां जल भराव वाले हिस्सों, नमक-चट्टानों और छोटी झाड़ियों की पारिस्थिति मिलती है, जो जीव और पक्षियों के लिए जीवन-धारा का काम करती है।

ताल छापर का मौसम शुष्क मरु-क्षेत्रीय है। सर्दियों (अक्टूबर से फरवरी तक) के दौरान तापमान ठंडा रहता है और यह बर्ड-वॉचिंग (पक्षी अवलोकन) के लिए उत्तम समय माना जाता है।

गौरतलब है कि पर्यटन मानचित्र पर अधिक संभावनाओं के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग, स्थानीय नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में समय-समय पर पक्षी उत्सव का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण हेतु जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ▪

हरित विकास की अपूर्व पहल

1.42 लाख फलदार पौधों से सजा 'भारत उपवन'

पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को साथ लेकर चलने वाले कार्यक्रम ही आज के समय में सतत विकास की वास्तविक आधारशिला बनाते हैं। बदलते जलवायु परिदृश्य, भूमि क्षरण और ग्रामीण संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच यदि चरागाह और राजस्व बंजर भूमि को पुनर्जीवित कर हरियाली में बदला जाए, तो यह केवल पर्यावरणीय सुधार नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण का भी सशक्त माध्यम बन सकती है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ जिला ब्यावर में "भारत उपवन कार्यक्रम" की शुरुआत की गई है, जिसने चरागाह संरक्षण और ग्राम समृद्धि की दिशा में एक मिसाल कायम की है।

सतीश सोनी, जनसम्पर्क अधिकारी

ग्राम स्तर पर सतत विकास का अभिनव प्रयोग

जिला ब्यावर की 73 ग्राम पंचायतों में 1228 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर 1 लाख 42 हजार 750 फलदार पौधों का रोपण किया गया है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, ग्राम पंचायतों की आर्थिक सशक्तता तथा वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम को जिले की 7 पंचायत समितियों की 216 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है।

हरित विकास मॉडल

कार्यक्रम के अंतर्गत चरागाह भूमि को सुरक्षित रखते हुए फलदार चरागाह विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना के अनुसार, कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। खण्ड विकास अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वित बैठकों में भूमि का चिन्हांकन, मिट्टी परीक्षण और विभिन्न योजनाओं—वीबी-जी राम जी, राज्य वित्त आयोग तथा केंद्र वित्त आयोग के कन्वर्जेंस के माध्यम से स्वीकृतियां सुनिश्चित की गईं।

सुदृढ़ सुरक्षा और दीर्घकालिक संरक्षण की व्यवस्था

पौधों की सुरक्षा हेतु तारबंदी एवं मेडबंदी की गई तथा स्थानीय जलवायु के अनुरूप फलदार पौधों का चयन कर वैज्ञानिक पद्धति से गड्ढों का उपचार कर प्रथम वर्षा में वृक्षारोपण किया गया। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की गई है। पौधों की देखरेख और सुरक्षा के लिए केयरटेकर नियुक्त किए गए हैं। उपवनों में मुख्यतः फलदार पौधे लगाए गए हैं, जबकि बाहरी परिधि पर नीम, पीपल और अन्य छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे पौधों की सुरक्षा के साथ पक्षियों को आश्रय और भोजन भी उपलब्ध हो सके।

पारदर्शिता और निगरानी

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ब्यावर डॉ. गोपाल लाल मीना ने बताया कि लगाए गए पौधों की जीवितता दर 90 प्रतिशत से अधिक है, जो कार्यक्रम की प्रभावशीलता का प्रमाण है। शेष 143 ग्राम पंचायतों में आगामी वित्तीय वर्ष में भारत उपवन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा सभी उपवनों की निरंतर निगरानी और निरीक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। वर्ष 2025-26 के अंतर्गत "भारत उपवन 2.1" चरण में 45 ग्राम पंचायतों में 62 हजार पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे पूर्ण रूप से हासिल किया गया। कुल 612 बीघा भूमि पर पौधारोपण कर सभी पौधों की जियो-टैगिंग भी सुनिश्चित की गई है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी दोनों सुदृढ़ हुई हैं।

भारत उपवन विकसित करने के निर्देश

"भारत उपवन" कार्यक्रम बहुआयामी लाभ प्रदान करने वाला मॉडल बनकर उभरा है। इससे पंचायत भूमि अतिक्रमण से सुरक्षित हो रही है, स्थानीय स्तर पर ताजे और सस्ते फलों की उपलब्धता बढ़ रही है, पंचायतों की आय में वृद्धि हो रही है, महिलाओं की सहभागिता सुदृढ़ हो रही है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है तथा रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही, पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता और स्वयं सहायता समूहों को खाद्य उत्पादों हेतु कच्चा माल भी प्राप्त हो रहा है। ▪

"राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी" और "राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर नीति"

खुल रहे आर्थिक विकास और समावेशी प्रगति के नए द्वार

डॉ. आशीष खंडेलवाल, उपनिदेशक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसी संकल्प को हमारे प्रदेश राजस्थान में तेज गति से साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने "राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026" और "राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर नीति 2024" जैसी क्रांतिकारी नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों ने न केवल राजस्थान को आईटी और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर, आर्थिक विकास और समावेशी प्रगति के नए द्वार भी खोल दिए हैं।

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी

हाल ही जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लॉन्च की गई राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "एआई फॉर ऑल" और "डिजिटल इंडिया" विजन से प्रेरित है। यह नीति तीन मजबूत स्तंभों पर टिकी है- गवर्नेंस में एआई को अपनाना, स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग तथा इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स। एआई-एमएल पॉलिसी से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता-संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेंगे। इस नीति से सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक त्वरित, नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी होगा तथा प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान की प्रक्रिया सरल की जाएगी, प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा तथा स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों को भी विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन में प्रभावी योगदान देते हुए राजस्थान को आईटी-आईटीईएस हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी-2026 लाई गई है। यह नीति सेवा प्रदायगी में

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी। नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर विशेष फोकस

नीति के अंतर्गत एआई प्रणालियों को पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष और गोपनीयता-संरक्षित बनाने पर विशेष बल दिया गया है। एआई सिस्टम्स में संभावित पक्षपात को कम करने, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्णय प्रक्रियाओं की स्पष्टता बनाए रखने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। नीति के अंतर्गत प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी।

स्कूल से कॉलेज तक एआई शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

नीति के तहत प्रत्येक विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एआई उपयोग की संभावनाओं की पहचान करेगा तथा एक एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूट अवसंरचना, एआई क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कार्मिकों के लिए विशेष एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और रिसर्च संस्थानों को एआई से जुड़ी पहलों के लिए आरआईपीएस, एमएसएमई और स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप-अप प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर नीति

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाने वाला राजस्थान डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) नीति इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह नीति न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की दृष्टि भी रखती है।

नीति का उद्देश्य और महत्त्व

राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी) जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी बनाना है। यह नीति राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर एवीजीसी-एक्सआर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और भारत भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार का यह कदम समय की मांग के अनुरूप है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं

इस नीति के तहत कई आकर्षक प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, कर छूट और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा, राज्य में एवीजीसी-एक्सआर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है, जो प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार का केंद्र होगा। नीति में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है, ताकि वे इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार सकें। गेमिंग और एनिमेशन उद्योग के लिए विशेष इन्क्यूबेशन सेंटर, तकनीकी पार्क और सह-कार्यस्थल (को-वर्किंग स्पेस) भी बनाए जाएंगे। साथ ही, नीति में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करने की रणनीति शामिल है, जिससे स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच मिल सके।

रोजगार और आर्थिक प्रभाव

एवीजीसी-एक्सआर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उद्योग अगले कुछ वर्षों में भारत में लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि इस नीति के जरिए राज्य में 50 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हों। यह न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, यह नीति पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, एक्सटेंडेड रियलिटी का उपयोग कर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों को डिजिटल रूप से रिक्रिएट किया जा सकता है, जिससे पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। ■

पूरे हाड़ौती क्षेत्र को मिली 'नई उम्मीद'

-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने 7 मार्च को कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। साथ ही, परवन अकावद पेयजल परियोजना एवं नौनेरा पेयजल परियोजना का भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों व माता-बहनों के लिए योजनाओं पर राजस्थान में तेजी से काम हो रहा है। कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शिलान्यास का दिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और एक नई उपलब्धि का दिन है। डेढ़ हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा की जनता से वादा किया था कि यहां एयरपोर्ट को साकार करके दिखाया जाएगा। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। इसमें समय लगता था और असुविधा भी होती थी, लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा, तो कोटा समेत आस-पास के पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी बढ़ेगा।

किसान, मजदूर, महिला, गरीब और युवा के उत्थान के लिए रोडमैप तैयार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसान, मजदूर, महिला, गरीब और युवा के उत्थान के लिए रोडमैप तैयार किया था। राज्य सरकार किसानों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम कर रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते पर काम हो रहा है। वहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के माध्यम से पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि उदयपुर में देवास परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। ब्राह्मणी नदी से जल संग्रहण एवं सोम-कमला-अम्बा परियोजना पर निरन्तर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र के लिए नवनेरा, ईसरदा एवं परवन अकावद परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर खेत को पानी और हर घर को पीने का जल पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

पर्यटन, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में नवीन संभावनाएं

केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार और सपना अब पूरा हुआ है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहां के लोगों के लिए पर्यटन, रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में नवीन संभावनाएं बनेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, यहां स्वागत एक परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा एक संकल्प है। श्री नायडू ने कहा कि 1 हजार 507 करोड़ रुपये की लागत से 20 हजार वर्ग मीटर का टर्मिनल बनाया जाएगा। 1100 एकड़ में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा।

आमजन का बहुत बड़ा सपना पूरा

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि दशकों से कोटा क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। शंभूपुरा में कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से हाड़ौती के आमजन का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोटा की धरती पर वर्ष 2023 में जो वादा किया था, वह आज पूरा हुआ है। ▪

टपूकड़ा संयंत्र में इसी साल शुरू होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन

राजस्थान में बनेगी होण्डा की पहली ईवी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 14 मार्च को मुख्यमंत्री कार्यालय में होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होण्डा के पहले ईवी मॉडल (होण्डा 0 अल्फा) का अनावरण किया। होण्डा की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के टपूकड़ा संयंत्र में बनेगा, जिसका उत्पादन इसी वर्ष शुरू होने जा रहा है। 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' की तैयारियों के तहत सितंबर 2024 में जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने होण्डा के शीर्ष प्रबंधन को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के आह्वान के समर्थन में राजस्थान में ईवी मॉडल निर्माण एवं निवेश के लिए आमंत्रित किया था। साथ ही, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, जिसको लेकर होण्डा के प्रतिनिधिमंडल ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

बैठक के दौरान कंपनी की ओर से भारत में अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए योजनाएं भी साझा की गई। साथ ही बताया गया कि यहां उत्पादित मेड इन इंडिया ईवी मॉडल घरेलू बाजार के साथ ही कई देशों में निर्यात किए जाएंगे।

पर्यावरणीय संतुलन के साथ औद्योगिक विकास

होण्डा टपूकड़ा संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने जा रही है, जो राजस्थान की प्रभावशाली निवेश नीतियों पर वैश्विक विश्वास का बेहतरीन प्रमाण है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की दिशा में इसके बाद और निवेश बढ़ने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने एवं पर्यावरणीय संतुलन के साथ औद्योगिक विकास की यात्रा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

प्रदेश की प्रभावशाली नीतियों का असर

होण्डा कम्पनी का राजस्थान से जुड़ाव काफी पुराना है। वर्ष 2007 में कम्पनी के संयंत्र का शिलान्यास, वर्ष 2014 में वाहनों का उत्पादन प्रारम्भ होना और अब वर्ष 2026 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले उत्पादन के लिए टपूकड़ा संयंत्र का चयन राजस्थान के लिए गर्व की बात है। प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ परिवहन की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ईवी खरीद पर अनुदान, सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ चार्जिंग स्टेशन्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्क्रैप कराने एवं नए वाहन की खरीद पर 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति' के तहत छूट भी दी जा रही है।

> "
> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरित ऊर्जा एवं ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही, देश के ऑटोमोटिव भविष्य में राज्य की मजबूत भूमिका के लिए निवेशों का समर्थन करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं होने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन यहां होने से अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी।
>
> **- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

ऑटो और ऑटोपार्ट्स की सप्लाई चेन का एक पूरा ईको-सिस्टम

टपूकड़ा संयंत्र भारत में होण्डा के लिए एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए कारों और पुर्जों का निर्माण करता है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कंपनी की ओर से लिया गया यह फैसला महत्त्वपूर्ण साबित होगा। होण्डा ने अपने सप्लायर्स और दोपहिया संयंत्र के जरिए राजस्थान में ऑटो और ऑटोपार्ट्स की सप्लाई चेन का एक पूरा ईको-सिस्टम तैयार किया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 मार्च को असम के गुवाहाटी में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के हस्तान्तरण कार्यक्रम तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन एवं उद्घाटन समारोह में जन समूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जुड़े और उनका संबोधन भी सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान देश की आत्मा है। इनके सम्मान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों किसान परिवारों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त हस्तान्तरित की है। इनमें राजस्थान के 66 लाख 76 हजार से अधिक किसान शामिल हैं, जिन्हें 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल राज्य सरकार की ओर से 3 हजार रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जा रही है। राज्य सरकार इस सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपये तक बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। फसल बीमा योजना में खराबे पर ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक 6 हजार 473 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम राज्य में वितरित किए जा चुके हैं।

घुमन्तु परिवारों को आवासीय पट्टे बच्चों के लिए छात्रावास

अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मन्दिर के सभागार में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबुद्धजन महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हुए उनके विकास को जरूरी बताया है। मिट्टी से जुड़े इस समुदाय के त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इसके कल्याण और सशक्तीकरण को लेकर समर्पित है।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से घुमन्तु परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं और परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गयी है। बजट वर्ष 2026-27 में घुमन्तु समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम की नींव रखी है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। साथ ही प्रवास-प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर तथा शैक्षिक संभागों में 6 माह के स्कूल रेडिनेस कैम्प भी आयोजित किए जाएंगे। जिससे विद्यालय से वंचित रहने वाले बच्चों तक शिक्षा प्राप्त हो सके।

'संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष' और 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' पुस्तकों का विमोचन

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तकों 'संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष: नवाचारों के दो वर्ष' और 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' के नवीन संस्करण का विमोचन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है और उसके सुझावों पर विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा की परंपराएं ऐतिहासिक रही हैं और संसदीय मूल्यों पर आधारित इस व्यवस्था को नवाचारों के माध्यम से नई ऊर्जा और दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए परंपरा और नवाचार के संतुलन के साथ जनभागीदारी और पारदर्शिता को आवश्यक बताया।

गौरव सेनानी समारोह में वीरों को नमन

झुंझुनूं में होगी वार म्यूजियम की स्थापना

चूरू में 8 मार्च को गौरव सेनानी समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। श्री शर्मा ने इस दौरान पूर्व सैनिकों का सम्मान किया और जॉब लेटर सौंपे। साथ ही, प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

राष्ट्र सेवा में राजस्थान के वीरों की अग्रणी भूमिका रही है। यहां के लगभग हर गांव में कोई न कोई ऐसा परिवार है, जिसने सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा की है। सैनिक वास्तव में कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वे जीवनभर राष्ट्रहित और समाजहित के लिए निरन्तर कार्य करते हैं। उनका त्याग और बलिदान से परिपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। चूरू और शेखावाटी की धरती ने देशप्रेम के भाव को सदैव जीवंत रखा है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है।

रक्षा क्षेत्र में देश बन रहा आत्मनिर्भर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति बन कर उभर रहा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।

एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्सेज में सभी सुविधाएं एक छत के नीचे

राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्पलेक्स का चरणबद्ध निर्माण कर रही है। इन कॉम्पलेक्सेज में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, सैनिक कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। प्रथम चरण में 36 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनूं में इन कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र और झुंझुनूं में 'वॉर म्यूजियम' की स्थापना भी की जाएगी।

विभिन्न विभागों में नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

राज्य सरकार सैनिक और उनके परिवारों को सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आरटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50 प्रतिशत और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत की छूट देने के साथ ही, नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रेक्सको के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 वर्ष में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की गई है।

सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. – 07

1. **भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया?**

a. अजमेर	b. जयपुर
c. भरतपुर	d. बांसवाड़ा

2. **देश का पहला जिंक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा?**

a. ब्यावर	b. जैसलमेर
c. जयपुर	d. भीलवाड़ा

3. **राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई?**

a. सतत भविष्य के लिए विज्ञान
b. विज्ञान में महिलाएं- विकसित भारत को उत्प्रेरित करना
c. स्वदेशी तकनीकें
d. सतत विकास के लिए नवाचार

4. **बजट 2026-27 में 'नशामुक्त राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई?**

a. Raj-Savera	b. Raj-Suraksha
c. Raj-Sankalp	d. Raj-Nasha Mukti Abhiyan

5. **राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?**

a. 50 लाख रुपये	b. 75 लाख रुपये
c. 1 करोड़ रुपये	d. 1.5 करोड़ रुपये

6. **भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनीं हैं?**

a. अंचल भाटेजा	b. थान्या नाथन
c. फातिमा बीवी	d. इंदु मल्होत्रा

7. **भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया?**

a. जोधपुर	b. जयपुर
c. रणकपुर	d. जैसलमेर

8. **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन कहां किया गया?**

a. कानपुर	b. जयपुर
c. लखनऊ	d. राजकोट

9. **भारतीय सेना का अभ्यास 'वज्र घात' कहां आयोजित किया गया?**

a. बीकानेर	b. बाड़मेर
c. जोधपुर	d. जैसलमेर

10. **हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ अपने 'डिजिलॉकर' प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?**

a. यूगांडा	b. नाइजीरिया
c. केन्या	d. दक्षिण अफ्रीका

11. **वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया जाता है**

a. 15 मार्च	b. 17 जनवरी
c. 6 मार्च	d. 20 फरवरी

12. **शुष्क बागवानी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?**

a. पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीक पर जोर
b. जैव विविधता और जलवायु अनुकूलनशीलता के माध्यम से टिकाऊ भविष्य का निर्माण
c. जैविक कृषि को बढ़ावा देना
d. कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को घटाना

13. **राजस्थान की पहली शुगरमिल कहां स्थित है?**

a. गंगानगर	b. रतनगढ़
c. भोपालसागर	d. लालगढ़

14. **गैर नृत्य राजस्थान में अधिकतर किस समुदाय द्वारा किया जाता है?**

a. भील	b. गुर्जर
c. जाट	d. बंजारा

15. **निम्नलिखित में से कौनसी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है?**

a. मालपुरा	b. नाली
c. मगरा	d. मालवी

16. **निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है?**

a. जूना खिला	b. कुंभलगढ़ किला
c. चित्तौड़गढ़ किला	d. आमेर किला

17. **पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर प्रमुख मंदिर कहां स्थित है?**

a. ओसियां	b. आसोतरा
c. सांभर	d. डीग

18. **राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है?**

a. 202349	b. 103189
c. 691943	d. 185095

प्रश्नोत्तरी नं. – 06 के उत्तर एवं विजेताओं का नाम

उत्तर : 1(b),2(a),3(c),4(a), 5(b),6(c),7(d),8(b),9(a),10(a),11(b), 12(a), 13(a), 14(d), 15(a),16(a),17(c),18(c),19(b)

सांवरमल सिहाग
सरदारशहर, चूरू

रामस्वरूप मिर्धा
कुचामन डीडवाना

हेमलता मालव
पीसाहेड़ा कोटा

राज्य सरकार की प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं तथा राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर 20 अप्रैल, 2026 तक ईमेल द्वारा **sujasconnect@gmail.com** पर प्रेषित करें।प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित प्रतिभागियों के फोटो सहित नाम एवं सही उत्तर 'राजस्थान सुजस' के आगामी अंक में प्रकाशित किए जाएंगे व प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को डीआईपीआर द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।

धरोहर

आस्था और शिल्प की अनुपम विरासत

अमर सागर जैन मंदिर, जैसलमेर

अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर की स्थापत्य विरासत का एक सुंदर उदाहरण है। सेठ हिम्मत रामजी द्वारा बनाया गया यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) जी को समर्पित है। पीले बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के स्तंभों, दीवारों और तोरण द्वारों पर अत्यंत सूक्ष्म कारीगरी देखने को मिलती है। पत्थरों पर उकेरी गई पुष्प आकृतियां, पारंपरिक अलंकरण इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। मंदिर की बनावट में कलात्मक जालियां, सुसज्जित मंडप और गुंबद इसकी स्थापत्य सुंदरता को और प्रभावशाली बनाते हैं।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

सांस्कृतिक पुनरुत्थान की पहल

ऐतिहासिक पहचान की पुनर्स्थापना

माउंट आबू (आबू राज), सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। इसका परिवर्तित नया नाम "आबू राज" क्षेत्र की प्राचीन पहचान अर्बुद पर्वत और अर्बुदा देवी मन्दिर से जुड़ा है।

कामां (भरतपुर) ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है जिसका इसका संबंध भगवान कृष्ण की कथाओं से माना जाता है।
इसका नया नाम "कामवन" प्राचीन कामवन नामक वन क्षेत्र की ऐतिहासिक मान्यता को दर्शाता है।

जहाजपुर (भीलवाड़ा) कस्बे का नाम बदलकर "यज्ञपुर" रखा गया है, जो इस क्षेत्र की प्राचीन वैदिक परंपराओं और यज्ञ संस्कारों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है।

वर्तमान सरकार का यह निर्णय प्रदेश की प्राचीन परंपराओं, धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक — सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त, राकेश शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
संपादक— डॉ. रजनीश शर्मा , मैसर्स कृष्णा प्रिन्टर्स, डी—14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, (18,000 प्रतियां) ' राजस्थान सुजस ' पृष्ठ संख्या 72 • अंक प्रतियां 1,00,000